गरवी गुजरात

RNI No. GUJHIN/2011/39228

GARVI GUJARAT

गरवी गुजरात

अहमदाबाद से प्रकाशित दैनिक

वर्ष : 15
अंक : 177
दि. 29.10.2025,
बुधवार
पाना : 04
किंमत : 00.50 पैसा

EDITOR : MANOJKUMAR CHAMPAKLAL SHAH Regd. Office: TF-01, Nanakram Super Market,Ramnagar,Sabarmati, Ahmedabad-380 005. Gujarat, India.

Phone : 90163 33307 (M) 93283 33307, 98253 33307 • Email : garvigujarat2007@gmail.com • Email : garvigujarat2007@yahoo.com • Website : www.garvigujarat.co.in

पाकिस्तान ने फिर तोड़ा सीजफायर, भारतीय चौकियों पर रातभर चली गोलाबारी – सेना ने दिया करारा जवाब, कई पाक ठिकाने तबाह

नई दिल्ली। एक बार फिर पाकिस्तान ने अपनी नापाक हरकतों को दोहराते हुए नियंत्रण रेखा (LoC) पर सीजफायर का उल्लंघन किया है। 26 और 27 अक्टूबर की दरमियानी रात पाकिस्तानी सेना ने जम्मू-कश्मीर के लीपा घाटी क्षेत्र में भारतीय चौकियों को निशाना बनाते हुए भारी गोलाबारी की। इस दौरान पाकिस्तान की ओर से छोटे हथियारों से फायरिंग के साथ-साथ मोर्टार भी दागे गए। भारतीय रक्षा सूत्रों के अनुसार, यह गोलीबारी पूरी तरह अकारण थी और इसका कोई उकसावा भारतीय सेना की ओर से नहीं हुआ था।

रक्षा मंत्रालय के सूत्रों ने बताया कि पाकिस्तानी फायरिंग देर रात लगभग 12:40 बजे शुरू हुई, जो करीब एक घंटे तक जारी रही। भारतीय सेना ने तत्काल मोर्चा संभालते हुए जवाबी कार्रवाई की और पाकिस्तान की कई पोस्टों को निशाना बनाया। बताया जा रहा है कि भारतीय सेना की जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तानी चौकियों को भारी नुकसान पहुंचा है।

भारतीय सेना के प्रवक्ता ने कहा कि "हमारी सीमा पर तैनात टुकड़ियाँ किसी भी अप्रत्याशित स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। दुश्मन की ओर से की गई हर उकसावे की कार्रवाई का माकूल और त्वरित जवाब दिया जाएगा। देश की सीमाओं की रक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और किसी भी सूरत में हमारे जवानों की सुरक्षा से समझौता नहीं किया जाएगा।"

स्थानीय सूत्रों के अनुसार, फायरिंग की आवाज़ कई किलोमीटर तक सुनाई दी। भारतीय सेना के जवानों ने जिस सटीकता से जवाबी कार्रवाई की, उससे पाकिस्तानी ठिकानों पर खासी दहशत फैल गई। भारतीय सेना ने रातभर सतर्कता बनाए रखी और स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है।

रक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि पाकिस्तान बार-बार सीजफायर तोड़कर भारत को उकसाने की कोशिश कर रहा है। विश्लेषकों के मुताबिक, पाकिस्तान की यह रणनीति उसकी घरेलू राजनीतिक और आर्थिक अस्थिरता से ध्यान भटकाने का प्रयास है। लगातार हो रही आतंकवादी गतिविधियों और जनता के विरोध प्रदर्शनों के बीच पाकिस्तानी सेना सीमापार तनाव पैदा कर जनता को भटकाना चाहती है।

अप्रैल 2025 में हुए पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारतीय सेना ने 'ऑपरेशन सिंदूर' के तहत पाकिस्तान समर्थित आतंकियों के ठिकानों पर हवाई हमले किए थे, जिनमें 100 से अधिक आतंकियों को मार गिराया गया था। उस अभियान के बाद दोनों देशों के बीच 10 मई को एक नया सीजफायर समझौता हुआ था, जिसे स्थायी शांति की दिशा में एक सकारात्मक कदम माना गया था। लेकिन पाकिस्तान के लगातार उल्लंघनों से एक बार फिर सीमा पर तनाव बढ़ने की आशंका पैदा हो गई है। सैन्य सूत्रों के अनुसार, भारतीय सेना की खुफिया इकाइयाँ इस बात का पता लगा रही हैं कि पाकिस्तानी सेना की गोलाबारी के पीछे क्या उद्देश्य था — क्या यह घुसपैठ कराने की कोशिश थी या आतंकी गतिविधियों को छिपाने की साजिश। सेना ने स्पष्ट किया है कि किसी भी नापाक हरकत का जवाब सीमा पर ही नहीं, बल्कि रणनीतिक स्तर पर भी दिया जाएगा।

भारतीय सीमाओं पर फिलहाल हालात नियंत्रण में हैं, लेकिन सुरक्षा एजेंसियों को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं। सीमा पर फायरिंग के चलते आसपास के गाँवों में दहशत का माहौल है, कई परिवारों को अस्थायी रूप से सुरक्षित स्थानों पर भेजा गया है। सीमा पार की हर हलचल पर भारतीय सेना की नज़र है, और इस बार पाकिस्तान को उसके हर हमले की भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है।

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राफेल में भरेंगी उड़ान, देश की रक्षा क्षमता और महिला नेतृत्व का नया इतिहास रचने को तैयार भारतीय वायुसेना

नई दिल्ली। आज का दिन भारतीय वायुसेना और पूरे देश के लिए ऐतिहासिक साबित होने जा रहा है, क्योंकि देश की प्रथम नागरिक और सशस्त्र बलों की सर्वोच्च कमांडर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अत्याधुनिक लड़ाकू विमान 'राफेल' में उड़ान भरने जा रही हैं। यह उड़ान हरियाणा के अंबाला वायुसेना स्टेशन से भरेगी, जहां वायुसेना की सबसे शक्तिशाली स्क्वाड्रन 'गोल्डन एरो' तैनात है। राष्ट्रपति का यह साहसिक कदम न केवल भारत की सैन्य क्षमता का प्रतीक बनेगा, बल्कि यह भी दर्शाएगा कि महिला नेतृत्व अब देश की रक्षा व्यवस्था के हर क्षेत्र में अपनी दृढ़ उपस्थिति दर्ज करा रहा है। राष्ट्रपति मुर्मू का यह दौरा केवल औपचारिकता नहीं, बल्कि एक प्रेरणादायक संदेश भी है — कि भारत का सर्वोच्च नेतृत्व राष्ट्र की सुरक्षा, साहस और तकनीकी उत्कृष्टता के साथ सीधा जुड़ाव रखता है। इस ऐतिहासिक उड़ान के लिए राष्ट्रपति को वायुसेना के विशेषज्ञ पायलटों ने विस्तृत जानकारी दी है, जिसमें विमान के नियंत्रण, सुरक्षा प्रोटोकॉल और आपातकालीन प्रक्रियाओं की जानकारी शामिल है। उड़ान से पहले उन्हें राफेल के कॉकपिट, नियंत्रण प्रणाली और अत्याधुनिक हथियारों के बारे में बताया गया। राफेल को दुनिया के सबसे शक्तिशाली मल्टीरोल फाइटर जेट्स में गिना जाता है, जिसमें हवा से हवा में और हवा से जमीन पर वार करने की अद्भुत क्षमता है। अंबाला वायुसेना स्टेशन इस उड़ान के लिए विशेष रूप से सजाया गया है। सुरक्षा के सख्त इंतज़ाम किए गए हैं और

वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल वी. आर. चौधरी सहित शीर्ष अधिकारी स्वयं उपस्थित रहेंगे। यह क्षण भारतीय वायुसेना के लिए गर्व का होगा जब देश की राष्ट्रपति, जो कि सशस्त्र बलों की सर्वोच्च कमांडर हैं, राफेल जैसे युद्धक विमान में उड़ान भरेंगी। राष्ट्रपति मुर्मू इससे पहले भी भारतीय वायुसेना की वीरता और कौशल का अनुभव कर चुकी हैं। 8 अप्रैल 2023 को उन्होंने असम के तेजपुर एयरबेस से सुखोई-30 एमकेआई में उड़ान भरी थी। उस अवसर पर उन्होंने कहा था कि भारतीय वायुसेना की प्रतिबद्धता, साहस और अनुशासन अद्वितीय है, और यह बल देश के गौरव और सुरक्षा की नींव है। उन्होंने तब यह भी कहा था कि हमारे सैनिकों की निष्ठा और समर्पण ही भारत की सीमाओं की सच्ची सुरक्षा है। आज जब राष्ट्रपति राफेल में उड़ान भरेंगी, तब यह दृश्य भारत के सामरिक इतिहास में एक अमिट छाप छोड़ जाएगा। यह उड़ान भारतीय नारी शक्ति, आधुनिक तकनीकी सामर्थ्य और राष्ट्रीय गौरव का एक संगम होगी। राष्ट्रपति का यह कदम आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बनेगा कि नेतृत्व का अर्थ केवल शासन नहीं, बल्कि देश की सुरक्षा और उसकी गरिमा के साथ आत्मिक जुड़ाव भी है।

दिल्ली हाईकोर्ट में तीन नए न्यायाधीशों ने संभाला कार्यभार, कुल संख्या हुई 44

नई दिल्ली। राजधानी की न्यायपालिका में मंगलवार का दिन ऐतिहासिक रहा, जब दिल्ली उच्च न्यायालय में तीन नए न्यायाधीशों ने अपने पद की शपथ ली। न्यायमूर्ति दिनेश मेहता, न्यायमूर्ति अवनीश झिंगन और न्यायमूर्ति चंद्रशेखरन सुधा ने दिल्ली हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय के समक्ष पद की शपथ ग्रहण की। शपथ ग्रहण समारोह के साथ ही अब दिल्ली हाई कोर्ट में न्यायाधीशों की कुल संख्या बढ़कर 44 हो गई है।

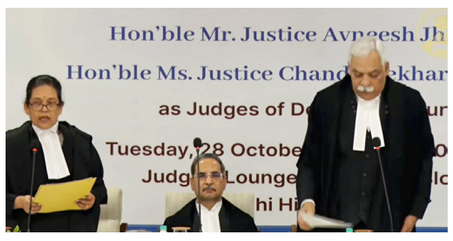

केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की सिफारिश के बाद 14 अक्टूबर को इन तीनों न्यायाधीशों के स्थानांतरण की अधिसूचना जारी की थी। न्यायमूर्ति दिनेश मेहता और न्यायमूर्ति अवनीश झिंगन को राजस्थान हाई कोर्ट से दिल्ली स्थानांतरित किया गया है, जबकि न्यायमूर्ति चंद्रशेखरन सुधा अब तक केरल हाई कोर्ट में अपनी सेवाएँ दे रही थीं। दिल्ली हाई कोर्ट में जजों की संख्या बढ़ाने की यह प्रक्रिया पिछले कुछ महीनों से निरंतर जारी है। हाल ही में छह अन्य न्यायाधीश — न्यायमूर्ति वी. कामेश्वर राव, न्यायमूर्ति नितिन वासुदेव साम्ब्रे, न्यायमूर्ति विवेक चौधरी, न्यायमूर्ति ओम प्रकाश शुक्ला, न्यायमूर्ति अनिल क्षेत्रपाल और न्यायमूर्ति अरुण कुमार मोंगा — ने भी विभिन्न उच्च न्यायालयों से स्थानांतरण के बाद दिल्ली में शपथ ली थी। हालांकि जुलाई में दिल्ली में पदभार संभालने वाले न्यायमूर्ति अरुण कुमार मोंगा को हाल ही में फिर से राजस्थान हाई कोर्ट स्थानांतरित कर दिया गया है।

कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि दिल्ली हाई कोर्ट में लंबित मामलों की भारी संख्या को देखते हुए यह तैनाती एक महत्वपूर्ण कदम है। न्यायपालिका में न्यायाधीशों की कमी लंबे समय से मुकदमों के निस्तारण में देरी का कारण रही है। नए न्यायाधीशों की नियुक्ति से अब न्यायिक प्रक्रिया की गति तेज होने की उम्मीद है, जिससे आम नागरिकों को शीघ्र और सुलभ न्याय प्राप्त करने में सहायता मिलेगी।

न्यायमूर्ति मेहता, झिंगन और सुधा के शामिल होने से न केवल न्यायिक क्षमता में विस्तार हुआ है, बल्कि यह कदम भारतीय न्याय व्यवस्था में पारदर्शिता और दक्षता को सुदृढ़ करने की दिशा में भी अहम माना जा रहा है। अब न्यायालय में न्याय की डिलीवरी को और अधिक प्रभावी व समयबद्ध बनाने की उम्मीद जताई जा रही है।

बिहार विधानसभा चुनाव का पहला चरण: अपराध और पूंजी का संगम

पटना। बिहार की राजनीति एक बार फिर अपराध और संपत्ति की चमक के बीच घिरी हुई नजर आ रही है। विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण में लोकतंत्र का यह महायज्ञ शुरू होने से पहले जो आंकड़े सामने आए हैं, वे राज्य की राजनीति की असल तस्वीर बयां करते हैं। छह नवंबर को होने वाले पहले चरण के मतदान में कुल 1314 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं, जिनमें से 1303 के शपथपत्रों का विश्लेषण किया गया। चौंकाने वाली बात यह है कि इनमें से 423 उम्मीदवारों यानी करीब 32 प्रतिशत के ऊपर आपराधिक मामले दर्ज हैं।

एडीआर और बिहार इलेक्शन वॉच की रिपोर्ट बताती है कि चुनाव में खड़े इन 1303 प्रत्याशियों में 354 उम्मीदवारों पर गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं, जो 27 प्रतिशत है। इन मामलों में हत्या, हत्या के प्रयास, महिलाओं पर अत्याचार और यहां तक कि बलात्कार जैसे संगीन आरोप शामिल हैं। रिपोर्ट के अनुसार, 33 उम्मीदवारों ने हत्या से संबंधित, 86 ने हत्या के प्रयास से संबंधित, 42 ने महिलाओं पर अत्याचार और 2 उम्मीदवारों ने बलात्कार से संबंधित मामले अपने शपथपत्र में घोषित किए हैं।

राजनीतिक दलों की स्थिति पर नजर डालें तो लगभग सभी प्रमुख पार्टियां इस गंदे पानी में अपने पैर भिगोती दिख रही हैं। आरजेडी के 70 में से 53 (76%), बीजेपी के 48 में से 31 (65%), कांग्रेस के 23 में से 15 (65%) और जेडीयू के 57 में से 22 (39%) उम्मीदवारों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। सबसे अधिक चिंताजनक स्थिति वामपंथी दलों की है, जहां सीपीआई और सीपीएम के सभी उम्मीदवारों ने अपने ऊपर आपराधिक मामले घोषित किए हैं।

गंभीर मामलों के तहत आरजेडी के 42, बीजेपी के 27, कांग्रेस के 12, और जेडीयू के 15 उम्मीदवारों पर गम्भीर धाराओं के तहत मामले हैं। सीपीआई (एमएल) के 14 में से 9 और लोजपा (रामविलास) के 13 में से 5 प्रत्याशी भी गंभीर अपराधों के आरोपी हैं। इससे साफ है कि बिहार की राजनीति में अपराधियों की हिस्सेदारी अब अपवाद नहीं, बल्कि परंपरा बन चुकी है।

दूसरी ओर, उम्मीदवारों की आर्थिक स्थिति पर नजर डालें तो यह चुनाव अमीरी की चमक से भी भरा है। पहले चरण के 1303 उम्मीदवारों में से 519 यानी लगभग 40 प्रतिशत करोड़पति हैं। उम्मीदवारों की औसत संपत्ति 3.26 करोड़ रुपये आंकी गई है। इसका अर्थ है कि बिहार की राजनीति में अब अपराध के साथ-साथ संपन्नता का गठजोड़ और मजबूत हुआ है।

शैक्षणिक दृष्टि से देखा जाए तो 519 उम्मीदवारों ने अपनी शिक्षा 5वीं से 12वीं के बीच बताई है, जबकि 651 उम्मीदवार स्नातक या उससे अधिक शिक्षित हैं। इस बार महिला उम्मीदवारों की हिस्सेदारी मात्र 9 प्रतिशत है, जो यह दर्शाता है कि राजनीति में महिलाओं की भागीदारी अब भी सीमित है।

यह पूरा परिदृश्य बिहार की चुनावी सच्चाई का आईना है — जहां एक ओर जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनने की तैयारी कर रही है, वहीं उम्मीदवारों की फेहरिस्त अपराध और पूंजी की जटिल कहानी कहती है। सवाल यह नहीं कि कौन जीतेगा, बल्कि यह है कि बिहार की जनता अपने भविष्य के लिए किस प्रकार की राजनीति को वैधता देने जा रही है — ईमानदारी की राजनीति या अपराध और धनबल की गठजोड़ वाली व्यवस्था को।

भारत पर टैरिफ लगाना अमेरिका की रणनीतिक चूक : जीना रायमोंडो का करारा प्रहार

वॉशिंगटन। अमेरिका की पूर्व वाणिज्य मंत्री जीना रायमोंडो ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की भारत को लेकर बनाई गई टैरिफ नीति पर तीखा प्रहार करते हुए कहा है कि भारत पर 50 प्रतिशत तक आयात शुल्क लगाना एक "गंभीर रणनीतिक भूल" है, जो न केवल आर्थिक रिश्तों को नुकसान पहुँचा रही है बल्कि अमेरिका की वैश्विक साख को भी कमजोर कर रही है। रायमोंडो ने कहा कि "ट्रंप की 'अमेरिका फर्स्ट' नीति अब 'अमेरिका अलोन' में बदल रही है," और इसके परिणामस्वरूप अमेरिका अपने पारंपरिक साझेदारों से दूर होता जा रहा है। हार्वर्ड कैनेडी स्कूल में एक संवाद के दौरान रायमोंडो ने खुलकर कहा कि भारत जैसे देश पर इतने ऊँचे टैरिफ लगाना आर्थिक दृष्टि से अव्यावहारिक है। उन्होंने कहा, "भारत केवल एक बड़ा व्यापारिक बाजार नहीं है, बल्कि हिंद-प्रशांत क्षेत्र में अमेरिका का एक अहम रणनीतिक सहयोगी भी है। ऐसे सहयोगी पर व्यापारिक बोझ डालना दीर्घकालिक कूटनीतिक संबंधों के लिए घातक साबित हो सकता है।" यह बयान सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर वायरल हो गया, और इसके बाद अमेरिकी नीति-निर्माताओं के बीच नई बहस छिड़ गई है। पूर्व मंत्री ने यह भी कहा कि ट्रंप प्रशासन की वर्तमान नीतियाँ न केवल वैश्विक व्यापार प्रणाली को अस्थिर कर रही हैं, बल्कि अमेरिका की "विश्वसनीय साझेदार" वाली छवि को भी नुकसान पहुँचा रही हैं। उन्होंने स्पष्ट चेतावनी दी कि यदि अमेरिका ने यूरोप, जापान और भारत जैसे मित्र देशों के साथ संबंधों को कमजोर किया, तो इसका परिणाम "मजबूत अमेरिका" नहीं बल्कि "अकेला अमेरिका" होगा। भारतीय परिप्रेक्ष्य में यह बयान ऐसे समय आया है जब भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय व्यापार समझौते (BTA) को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। मौजूदा समय में अमेरिका, भारत का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझीदार है, और बढ़े हुए आयात शुल्क का सीधा असर भारतीय निर्यातकों और विशेषकर तकनीकी, फार्मास्युटिकल व टेक्सटाइल उद्योग पर पड़ सकता है। विशेषज्ञों के अनुसार, यह नीति भारत-अमेरिका आर्थिक रिश्तों में तनाव को जन्म दे सकती है। भारतीय आर्थिक विश्लेषकों का मानना है कि इस परिस्थिति में भारत को "आत्मनिर्भर भारत" मिशन पर और बल देना चाहिए, ताकि विदेशी नीतियों के उतार-चढ़ाव से देश की अर्थव्यवस्था प्रभावित न हो। उनका कहना है कि यदि अमेरिका अपनी संरक्षणवादी नीति जारी रखता है, तो भारत को यूरोपीय संघ, दक्षिण-पूर्व एशिया और अफ्रीका जैसे नए व्यापारिक मार्गों को प्राथमिकता देनी होगी। ध्यान देने योग्य है कि जीना रायमोंडो वही नेता हैं जिन्होंने ट्रंप प्रशासन के दौरान अमेरिकी वाणिज्य विभाग का नेतृत्व किया था, और उनकी यह आलोचना न केवल प्रशासन की नीति पर प्रश्नचिह्न लगाती है, बल्कि रिपब्लिकन पार्टी के भीतर भी मतभेदों को उजागर करती है। अमेरिकी राजनीतिक हलकों में अब यह चर्चा तेज हो गई है कि क्या ट्रंप की टैरिफ नीति "अमेरिका की आर्थिक आत्मनिर्भरता" को मजबूत कर रही है या उसे वैश्विक स्तर पर अलग-थलग कर रही है। अंतरराष्ट्रीय विश्लेषकों के अनुसार, भारत पर 50 प्रतिशत तक टैरिफ का असर सिर्फ व्यापारिक आंकड़ों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि यह हिंद-प्रशांत क्षेत्र में रणनीतिक समीकरणों को भी प्रभावित कर सकता है। भारत, अमेरिका के लिए चीन के बढ़ते प्रभाव को संतुलित करने वाला सबसे विश्वसनीय साझेदार माना जाता है। ऐसे में वॉशिंगटन की यह आर्थिक नीति न केवल व्यापारिक असंतुलन पैदा कर रही है, बल्कि दीर्घकालिक कूटनीतिक हितों को भी कमजोर कर रही है।

इंसानियत का पैगाम: जमीयत उलमा-ए-हिंद धर्म नहीं, दर्द देखती है

नई दिल्ली। इस दौर में जब समाज धर्म और जाति की दीवारों में बंटा नजर आता है, उसी वक्त मौलाना अरशद मदनी के नेतृत्व में जमीयत उलमा-ए-हिंद ने फिर यह साबित किया है कि इंसानियत सबसे बड़ा मज़हब है। पंजाब, जम्मू और हिमाचल प्रदेश में आई भीषण बाढ़ के बाद जहां कई संगठन राहत कार्यों में पीछे हट गए, वहीं जमीयत ने बिना किसी भेदभाव के सबसे पहले मदद का हाथ बढ़ाया। मौलाना मदनी ने साफ शब्दों में कहा, "हम किसी का धर्म नहीं देखते, हम सिर्फ इंसान देखते हैं। जो मज़हब देखकर मदद करते हैं, वे इंसानियत की असल तालीम से अनजान हैं।"

पंजाब, जम्मू और हिमाचल में आई इस आपदा ने हजारों परिवारों को बेघर कर दिया। जब बाढ़ का पानी उतरने लगा, तब जमीयत की टीमें सबसे पहले प्रभावित इलाकों में पहुंचीं। जमीयत ने अपने स्वयंसेवकों को गाँव-गाँव भेजकर यह सुनिश्चित किया कि कोई भी पीड़ित भूखा न रहे और हर व्यक्ति तक राहत पहुँच सके। संगठन ने सिर्फ राशन या कपड़े ही नहीं बाँटे, बल्कि जिनके घर पूरी तरह तबाह हो गए, उनके लिए स्थायी आश्रय बनाने की योजना शुरू की।

जमीयत के सर्वे के बाद निर्णय लिया गया कि जिन परिवारों को सरकारी सहायता नहीं मिली है, उनके लिए नए मकान बनाए जाएंगे। जम्मू के उधमपुर ज़िले में पहले चरण में 15 घरों का निर्माण शुरू किया गया है। वहीं पंजाब के फ़ाज़िल्का में जमीयत की टीम ने 33 प्रभावित परिवारों को राहत सामग्री और पचास-पचास हज़ार रुपये की आर्थिक मदद दी। इनमें सात हिंदू परिवार भी शामिल थे — जो इस बात का प्रतीक है कि जमीयत की सेवा सीमाओं और मज़हबी पहचान से परे है।

मौलाना मदनी ने कहा कि "आपदा जब आती है, तो वह किसी से यह नहीं पूछती कि तुम हिन्दू हो या मुसलमान। इसलिए मदद भी सबकी होनी चाहिए।" उन्होंने बताया कि देशभर में जमीयत की शाखाएँ लगातार राहत और पुनर्वास कार्यों में लगी हैं। इससे पहले भी केरल की बाढ़ हो या असम में आई आपदा — जमीयत ने हर बार इंसानियत को अपना मज़हब मानकर काम किया है। राहत के इस अभियान में देशभर के मुसलमानों ने भी दिल खोलकर योगदान दिया। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, महाराष्ट्र और गुजरात से राहत सामग्री की गाड़ियाँ लगातार पंजाब और हिमाचल पहुँचती रहीं। इतनी मदद जुटी कि कई जगहों पर प्रशासन को कहना पड़ा कि अब राहत सामग्री पर्याप्त हो गई है।

मौलाना अरशद मदनी ने कहा, "हमारी जमीयत हमेशा मोहब्बत, भाईचारे और इंसानियत की बुनियाद पर खड़ी रहेगी। जो लोग समाज में नफ़रत का ज़हर घोल रहे हैं, उन्हें यह देखना चाहिए कि असली ताकत प्यार और सेवा में है, न कि विभाजन में।"

बाढ़ की इस त्रासदी के बीच जमीयत की यह पहल सिर्फ राहत अभियान नहीं, बल्कि एक नैतिक संदेश भी है — कि जब दुनिया दीवारें खड़ी कर रही है, तब भी कुछ लोग ऐसे हैं जो पुल बना रहे हैं, और उन पुलों का नाम है इंसानियत।

संपादकीय

बेरोजगारी की बेड़ियां

अमानवीयता की हद पार करती अमेरिका इमिग्रेशन एंड कस्टम इन्फोर्समेंट एजेंसी के संवेदनहीन तौर-तरीकों का त्रास झेलते 54 हरियाणवी युवा शनिवार को दिल्ली हवाई अड्डे पर उतरे। सुनहरे सपनों की आस लिए अमेरिका गए इन युवाओं ने जिन त्रासदियों का सामना किया, वो उन युवाओं के लिये सबक भी है, जो अपनी योग्यता व क्षमता का मूल्यांकन किए बिना बस विदेश जाने की धुन में लगे रहते हैं। निस्संदेह, इन युवाओं ने बेहतर भविष्य के लिये रिस्क लेने का जज्बा तो दिखाया, लेकिन एजेंटों के छलावे के चलते डंकी रूट पर फिसल गए। इन युवाओं को इस बात का भान नहीं रहा कि घोर दक्षिणपंथी रुझान वाले ट्रंप के शासन में प्रवासियों के साथ कैसी क्रूरता व भेदभाव किया जा रहा है। जिसके चलते उनके साथ अमेरिका में अपराधियों जैसा सुलूक किया है। उन्हें जेल और अपराधियों के लिये बने कैंपों में रखा गया। युवाओं ने आरोप लगाया कि जेलों में गर्मी में हीटर और सर्दी में एसी चलाकर रखा जाता था। शाकाहारियों को मांस दिया जाता था और न खाने पर सिर्फ सूखी रोटी। खेत बेचकर-कर्ज लेकर उज्ज्वल भविष्य के लिये अमेरिका गए युवा अपराधियों की तरह स्वदेश लौटे। समाचार माध्यमों में प्रकाशित चित्रों में इन हताश युवाओं को अपराधबोध से ग्रसित देखा गया। विडंबना देखिए कि कई युवा अपना खेत बेचकर और चालीस-पचास लाख एजेंट को देकर विदेश गए, लेकिन डंकी रूट में धकेल दिए गए। उस खतरनाक रास्ते पर जहां हर पल मौत का खतरा बना रहता है। परिवार वालों को इस बात का सुकून जरूर होगा कि कम से कम उनके बच्चे सकुशल तो घर लौट आए है। वो बात अलग है कि इन युवाओं को अपने असफल प्रयास का मलाल जीवनपर्यंत सालता रहेगा। कुछ युवा इससे अवसादग्रस्त हो सकते हैं। कुछ हताश युवा भटकाव की राह में गुजर सकते हैं। निश्चय ही यह घटनाक्रम इन युवाओं के लिये एक त्रासदी से कम नहीं रहेगा। सुखमय जीवन की आस ने नारकीय जीवन जीने को मजबूर कर दिया। वे बेड़ियों में देश लौटे। बहरहाल, इन युवाओं की अपमानजनक वापसी कई ज्वलंत सवालों को भी जन्म देती है। यह हमारी नीति-नियंताओं की विफलता ही है कि हम युवाओं को उनकी योग्यता के अनुसार काम नहीं दे पा रहे हैं। हम कहते नहीं थकते कि भारत दुनिया में सबसे ज्यादा आबादी वाला देश है। सवाल यह है कि इस युवा शक्ति को दिशा देने के लिये हमने क्या किया? तमाम प्रलोभन व लोकलुभावने वादे करने वाले राजनीतिक दलों की प्राथमिकता युवाओं को रोजगार देना क्यों नहीं होती? सिर्फ चुनाव आने पर करोड़ों रोजगार देने के वादे तो किए जाते हैं, लेकिन सत्ता में आने के बावजूद वे पूरे नहीं होते। दोष हमारी शिक्षा व्यवस्था का भी है जो डिग्री तो देती है, लेकिन रोजगार की गारंटी नहीं देती। दोष हमारी युवा पीढ़ी की उस मानसिकता का भी है जो सिर्फ नौकरी और उसमें भी सरकारी नौकरी को प्राथमिकता देती है। निजी क्षेत्र भी सिर्फ मुनाफे को प्राथमिकता देता है और तकनीक के जरिये रोजगार के अवसरों में कटौती को प्राथमिकता देता है। ऐसे देश में, जहां आबादी आज दुनिया में सबसे ज्यादा है, हमें श्रम प्रधान उद्योगों को प्राथमिकता देनी चाहिए। जिसमें अधिक लोगों को रोजगार मिल सके। कायदे से देश में बेरोजगारी का ग्राफ देखते आने वाले दशकों के लिये रोजगार का रोडमैप बनना चाहिए। लेकिन सत्ता भी सस्ती लोकप्रियता वाले कामों के जरिये अपना वोट बैंक सुधारने में लगी रहती है। यहां सवाल युवाओं व अभिभावकों की सोच का भी है, जो खेत बेचकर बेटे को विदेश भेजने की फिराक में रहते हैं। जितना पैसा उन्होंने विदेश भेजने वाले एजेंटों को दिया, उसमें क्या वे स्वरोजगार नहीं कर सकते थे? माना कि आज खेती-किसानी युवाओं को नहीं लुभाती, लेकिन वे इस खेत पर गैर परंपरागत खेती व फल-फूल आदि नकदी फसलों के विकल्प तो तलाश सकते हैं। सवाल हमारी प्रवर्तन एजेंसियों पर है कि क्यों युवाओं को विदेश भेजने वाले एजेंटों पर कार्रवाई नहीं करती, जो लाखों रुपये लूटकर इन्हें नर्क में धकेल देते हैं। वापस आए इन युवाओं के जरिये उन तक पहुंचा जा सकता है।

नया सैन्य गठजोड़ भारत के लिये चुनौती

> सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच हुआ हालिया रक्षा समझौता इस बात का संकेत है कि पाकिस्तान अब अपनी सुरक्षा रणनीति को क्षेत्रीय स्तर पर फैलाने में सफल हो रहा है। यह समझौता इस सिद्धांत पर आधारित है कि अगर किसी एक देश पर हमला होता है तो दोनों की संयुक्त प्रतिक्रिया होगी।

हाल ही में पाकिस्तान समेत संयुक्त अरब अमीरात, कतर और अज़रबैजान के बीच बन रहे सैन्य गठजोड़ की खबरें भारत के लिए गंभीर चिंता का विषय हैं। यह घटनाक्रम न केवल दक्षिण एशिया बल्कि मध्य एशिया और खाड़ी क्षेत्र के भू-राजनीतिक समीकरणों को भी प्रभावित कर रहा है। पाकिस्तान लगातार अपनी रक्षा और कूटनीतिक स्थिति को मज़बूत करने की दिशा में सक्रिय हुआ है और वह ऐसे देशों से निकटता बढ़ा रहा है जो भारत के रणनीतिक हितों के लिए चुनौती बन सकते हैं। भारत को इस नए उभरते गठजोड़ को केवल एक सामान्य रक्षा समझौते के रूप में नहीं देखना चाहिए, बल्कि इसे एक दीर्घकालिक रणनीतिक प्रयास के रूप में समझना चाहिए, जिसका उद्देश्य पाकिस्तान की अंतरराष्ट्रीय स्थिति को सुधारना और भारत पर अप्रत्यक्ष दबाव बनाना है। भारत की विदेश नीति और सुरक्षा के मद्देनजर इस तरह के गठबंधन बड़ी चुनौती के लिहाज देखे जाने चाहिए। पिछले महीने पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच हुए ऐतिहासिक सैन्य समझौते, जिसके तहत एक देश पर हुआ हमला दूसरे देश पर भी माना जाएगा, की तर्ज पर ही इस सैन्य गठजोड़ का विचार सामने लाया गया है। हालांकि इन चार देशों के बीच अभी कोई औपचारिक समझौता नहीं हुआ है, लेकिन माना जा रहा है कि अगले कुछ महीनों में इसकी घोषणा हो जाएगी। गौरतलब है कि तुर्किये, पाकिस्तान और अजरबैजान का त्रिपक्षीय गठबंधन, जिसे श्री ब्रदर्स के नाम से जाना जाता है, एक मजबूत सैन्य साझेदारी का रूप ले चुका इसके अतिरिक्त, इस्लामिक मिलिट्री काउंटर टेररिज्म कोएलिशन (आईएमसीटीसी) भी है, जिसका संस्थापक सऊदी अरब है और जिसमें चालीस से अधिक सदस्य देश शामिल हैं। इन देशों के बीच सैन्य अभ्यास, हथियार सौदे और कश्मीर जैसे मुद्दों पर इनका स्वाभाविक सामूहिक रुख भारत के लिए चिंता का विषय रहा है। इससे पाकिस्तान अपनी कुचालों का जायज ठहराने एवं अपनी रक्षा की गुहार लगाते हुए भारत पर दबाव बनाना चाहता है।

नहीं भूलना चाहिए कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद जब भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया, तब ज्यादातर मुस्लिम देशों ने तटस्थ रुख अपनाया था, लेकिन तुर्किये और अजरबैजान दो ऐसे मुल्क थे, जो पूरी तरह से पाकिस्तान के समर्थन में खड़े थे। दरअसल, तुर्किये के राष्ट्रपति तैयब अर्दोआन की इस्लामिक दुनिया के मॉडर्न खलीफा बनने की सनक का पाकिस्तान समर्थन करता है, इसी वजह से तुर्किये ने संयुक्त राष्ट्र में भी कश्मीर पर पाकिस्तान के रुख का खुला समर्थन किया है।

इसे भी पढ़ें: संतुलन, संयम और सक्रियता जयशंकर की पहचान, निकाल दिया भारत-अमेरिका रिश्तों में आई 'समस्या' का समाधान!

सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच हुआ हालिया रक्षा समझौता इस बात का संकेत है कि पाकिस्तान अब अपनी सुरक्षा रणनीति को क्षेत्रीय स्तर पर फैलाने में सफल हो रहा है। यह समझौता इस सिद्धांत पर आधारित है कि अगर किसी एक देश पर हमला होता है तो दोनों की संयुक्त प्रतिक्रिया होगी। यह बात भारत के लिए सीधे तौर पर खतरे की घंटी है क्योंकि इससे पाकिस्तान को रक्षा सहायता, प्रशिक्षण, संसाधन और राजनीतिक समर्थन प्राप्त हो सकता है। इसी तरह पाकिस्तान अज़रबैजान, यूएई और कतर जैसे देशों के साथ भी अपने संबंधों को मजबूत करने में जुटा है। इन देशों के साथ पाकिस्तान का यह बढ़ता सामरिक सहयोग उसके लिए आर्थिक और तकनीकी लाभ भी लेकर आ सकता है, जिससे भारत के लिए क्षेत्रीय संतुलन बनाए रखना कठिन हो सकता है। भारत को इन परिस्थितियों में अपनी विदेश नीति को अधिक सशक्त और लचीला बनाना होगा। अब वह समय बीत चुका है जब भारत केवल पारंपरिक प्रतिद्वंद्विता और सीमित क्षेत्रीय चिंताओं के आधार पर नीति बनाता था। आज की दुनिया में भू-राजनीति बहुस्तरीय हो चुकी है, जहां आर्थिक संबंध, तकनीकी साझेदारी और रक्षा सहयोग एक-दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं। भारत को चाहिए कि वह अपने खाड़ी देशों से संबंधों को और सुदृढ़ करे। यूएई और सऊदी अरब जैसे देशों के साथ भारत के आर्थिक और सांस्कृतिक संबंध पहले से ही मजबूत हैं, पर उन्हें रक्षा सहयोग के स्तर पर भी विस्तारित करने की जरूरत है। भारत यदि इन देशों के साथ रणनीतिक साझेदारी बढ़ाता है तो पाकिस्तान को क्षेत्रीय स्तर पर अलग-थलग करने में मदद मिल सकती है।

साथ ही भारत को यह भी समझना होगा कि पाकिस्तान केवल सैन्य ताकत पर नहीं, बल्कि कूटनीतिक चालों और मीडिया नैरेटिव के माध्यम से भी अपनी स्थिति को मजबूत करने का प्रयास कर रहा है। ऐसे में भारत को न केवल रक्षा मोर्चे पर बल्कि कूटनीतिक और सूचनात्मक मोर्चे पर भी सक्रिय रहना होगा। भारत की नीति प्रतिक्रियात्मक न होकर सक्रिय, दूरगामी और अग्रदर्शी होनी चाहिए। भारत को यह दिखाना होगा कि वह केवल अपनी सीमाओं की रक्षा तक सीमित नहीं है, बल्कि क्षेत्रीय स्थिरता और वैश्विक शांति का भी एक भरोसेमंद संरक्षक है। भारत ही दुनिया से आतंकवाद को समाप्त करने की मुहिम छेड़े हुए है। भारत के लिए यह भी जरूरी है कि वह अपने मित्र देशों के साथ सामूहिक सुरक्षा दृष्टिकोण विकसित करे। जिस तरह अमेरिका और यूरोपीय संघ सामूहिक रक्षा नीति पर चलते हैं, उसी तरह भारत को भी इंडो-पैसिफिक क्षेत्र, एसोसिएशन ऑफ साउथइस्ट ऐशियन नेशनस् -देशों और मध्य पूर्व में सहयोगी नेटवर्क को सुदृढ़ करना चाहिए। यह केवल सैन्य दृष्टि से नहीं बल्कि कूटनीतिक और आर्थिक दृष्टि से भी भारत की स्थिति को मजबूत करेगा।

पाकिस्तान की नई विदेश नीति की दिशा साफ है- वह भारत को घेरने की कोशिश कर रहा है, चाहे वह चीन के साथ सीपेक परियोजना के माध्यम से हो या अब मध्य-पूर्व के देशों के साथ रक्षा सहयोग के जरिए। भारत को इस घेराबंदी को तोड़ने के लिए तीन दिशा में एक साथ काम करना होगा- अपनी रक्षा क्षमता को आधुनिक बनाना, विदेश नीति में सक्रियता लाना, और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत की सकारात्मक छवि को और प्रखर बनाना। यह स्थिति भारत के लिए केवल एक चुनौती नहीं बल्कि अपनी सामरिक दूरदर्शिता को सिद्ध करने का अवसर भी है। भारत यदि समय रहते अपने पड़ोस में बढ़ते इस सैन्य गठजोड़ की गंभीरता को समझ लेता है और सक्रिय कदम उठाता है, तो वह न केवल पाकिस्तान की कूटनीतिक चालों को निष्प्रभावी बना सकता है, बल्कि दक्षिण एशिया को स्थिरता और सहयोग के नए मॉडल के रूप में प्रस्तुत कर सकता है।

इन चार राष्ट्रों का सैन्य गठबंधन भारत के लिए एक चेतावनी है कि भू-राजनीति में देशों के बीच धार्मिक एकजुटता नए रूप में सामने आ रही है, ऐसे में क्षेत्रीय शांति और सुरक्षा बनी रहे, इसके लिए भारत को अपनी रक्षा क्षमताओं को मजबूत करते हुए कूटनीतिक मोर्चे पर भी सक्रिय बने रहना होगा। भारत पिछले कई वर्षों से पाकिस्तान, तुर्की और अजरबैजान को काउंटर करने के लिए अलग-अलग रणनीतियों पर काम कर रहा है। इनमें इन तीनों देशों के दुश्मनों की मदद से लेकर इन्हें आर्थिक तरीके से चोट पहुंचाना भी शामिल है। पाकिस्तान के खिलाफ भारत के कदमों से हर कोई परिचित है। अब बात करते हैं तुर्की की। भारत ने तुर्की को काउंटर करने के लिए उसके सबसे बड़े दुश्मन ग्रीस के साथ रक्षा संबंधों को मजबूत किया है। इसके अलावा भारत ने साइप्रस के मुद्दे को भी अंतरराष्ट्रीय मंचों पर उठाना शुरू किया है, जिसकी जमीन पर तुर्की ने अवैध रूप पर कब्जा जमाया हुआ है। वहीं, भारत ने तुर्की को अपने बाजार में प्रवेश को लेकर भी सख्तियां बरती है।

इस सैन्य गठजोड़ के हकीकत बनने की सूरत में भारत के लिए जरूरी होगा कि वह आर्मेनिया, ग्रीस और साइप्रस के साथ अपने संबंध मजबूत करे और यूएई के साथ भी द्विपक्षीय रिश्तों को और प्रगाढ़ बनाए, जो भारत का बड़ा व्यापारिक भागीदार रहा है और आम तौर पर इस्लामिक मुद्दों पर तटस्थ रुख रखता है।आज भारत को यह मानना होगा कि "सुरक्षा" अब केवल हथियारों का मामला नहीं है, यह अर्थव्यवस्था, कूटनीति, और तकनीक का समन्वित प्रश्न बन चुका है। पाकिस्तान की नई चालें एवं कुचालें हमें केवल सतर्क रहने की नहीं, बल्कि सजग, सक्रिय और रणनीतिक रूप से एक कदम आगे रहने की प्रेरणा देती हैं। भारत यदि अपनी नीति में इस नए दृष्टिकोण को शामिल करता है, तो यह गठजोड़ उसके लिए खतरा नहीं बल्कि आत्मसुधार और आत्मसशक्तिकरण का अवसर साबित हो सकता है।

प्रेरणा

हिमालय की बेटी बनी अंग्रेज युवती : सरला बहन की अमर गाथा

ब्रिटेन की शांत वादियों में जन्मी कैथरीन मेरी हाइलामन का जीवन उस समय एक अप्रत्याशित मोड़ लेता है, जब वे 1932 में भारत की धरती पर आती हैं। वह दौर औपनिवेशिक शासन का था, जब भारत अंग्रेजी सत्ता के अधीन था, किंतु कैथरीन का भारत आगमन किसी शासन या शक्ति की लालसा से नहीं, बल्कि आत्मा की खोज और सत्य की अनुभूति से प्रेरित था। भारत के तीर्थस्थलों की दिव्यता, ऋषियों की तपोभूमि और यहां के जनजीवन की सरलता ने उनके हृदय को गहराई से स्पर्श किया। उन्हें लगा कि इस भूमि में कोई ऐसी अदृश्य ऊर्जा है जो आत्मा को शुद्ध कर देती है।

कैथरीन जब महात्मा गांधी के विचारों से प्रभावित होकर वर्धा स्थित उनके आश्रम पहुंचीं, तो उन्हें वहां के वातावरण ने मोह लिया। गांधी जी से मिलने पर यह विदेशी युवती भारतीय संस्कृति के प्रति अपने प्रेम और सेवा भाव को प्रकट करती है। गांधी जी उसकी निष्ठा से अत्यंत प्रभावित हुए। उन्होंने कहा, "यदि तुम भारत की सच्ची सेवा करना चाहती हो, तो पहले उसकी भाषा को अपनाओ। हिंदी ही वह सेतु है, जिसके माध्यम से तुम भारतवासियों के हृदय तक पहुंच सकती हो।" यह वाक्य कैथरीन के जीवन का नया मार्ग बन गया। उन्होंने निश्चय किया कि अब वे इस देश की मिट्टी में रच-बस जाएंगी और इसकी सेवा में अपने जीवन का प्रत्येक क्षण समर्पित करेंगी।

कैथरीन ने हिंदी सीखी, भारतीय रीति-रिवाजों को आत्मसात किया और उत्तराखंड के अल्मोड़ा क्षेत्र को अपनी कर्मभूमि बना लिया। वहां के कठिन जीवन, ऊबड़-खाबड़ रास्तों और विपन्न जनजीवन को देखकर उन्होंने ठान लिया कि वे इन लोगों के जीवन में प्रकाश लाएंगी। उन्होंने ग्राम-ग्राम जाकर महिलाओं को शिक्षा के महत्व से अवगत कराया, उन्हें साक्षर बनने, आत्मनिर्भर होने और अपने अधिकारों को समझने की प्रेरणा दी। धीरे-धीरे वे "सरला बहन" के नाम से प्रसिद्ध हुईं। यह नाम उन्हें स्थानीय लोगों ने उनके सादे स्वभाव और मातृत्व से भरे व्यवहार के कारण दिया था।

सरला बहन केवल शिक्षिका या समाजसेविका नहीं थीं, वे प्रकृति की सच्ची साधिका भी थीं। जब उन्होंने देखा कि पर्वतीय क्षेत्रों में वृक्षों की अंधाधुंध कटाई हो रही है और नदियों का स्वच्छ जल धीरे-धीरे प्रदूषित होता जा रहा है, तो वे गहरी चिंता में डूब गईं। उन्होंने समझा कि प्रकृति के बिना मानव का अस्तित्व ही असंभव है। इस विचार से प्रेरित होकर उन्होंने अपने अनुभवों को 'संरक्षण या विनाश' नामक पुस्तक में संकलित किया, जो पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक दस्तावेज के समान है। वे बार-बार कहती थीं कि अगर हम वृक्षों और नदियों की रक्षा नहीं करेंगे, तो आने वाली पीढ़ियाँ केवल विनाश देखेंगी।

उनका जीवन सादगी, त्याग और निस्वार्थ सेवा का प्रतीक बन गया। उन्होंने स्वयं को पूरी तरह भारतीय जीवन में ढाल लिया — भारतीय वस्त्र पहने, भारतीय भोजन अपनाया और भारतीय संस्कृति के प्रति उसी श्रद्धा से जुड़ीं, जैसे कोई सनातनी साधक अपने धर्म से जुड़ा होता है। उन्होंने कभी अपने ब्रिटिश मूल का गर्व नहीं किया, बल्कि कहा, "भारत ने मुझे पुनर्जन्म दिया है। यह भूमि केवल मेरी कर्मभूमि नहीं, मेरी मातृभूमि है।" अपने जीवन के अंतिम दिनों में जब वे शारीरिक रूप से कमजोर पड़ गईं, तब भी उनका मन हिमालय के संरक्षण और गंगा की पवित्रता में रमा रहा। नैनीताल के स्वतंत्रता सेनानी बैंकलाल कंसल से उन्होंने कहा था, "मेरे जीवन की सबसे बड़ी अनुभूति यही है कि यदि हिमालय को बचाना है, तो इसके हरे-भरे पेड़ों और गंगा जैसी पवित्र नदियों को बचाना ही सबसे बड़ी प्राथमिकता होनी चाहिए। यही जीवन का सच्चा धर्म है।"

आज सरला बहन भले ही इस पृथ्वी पर नहीं हैं, लेकिन उनकी आत्मा हिमालय की हवाओं में, गंगा की धारा में और पहाड़ों के हर उस वृक्ष में जीवित है जिसे उन्होंने बचाने का संदेश दिया था। एक विदेशी युवती जिसने भारत को अपनी आत्मा बना लिया, जिसने सेवा को अपना धर्म और प्रकृति की रक्षा को अपना तप माना — वह थीं सरला बहन, जो आज भी उत्तराखंड की वादियों में "हिमालय की बेटी" के रूप में अमर हैं।

कमजोर पड़ते लोकतांत्रिक मूल्य, मूलभूत सिद्धांतों को पुनर्स्थापित करना जरूरी

इस समय वे युवा चर्चा में हैं, जो कार्यकारी जीवन में प्रवेश कर चुके हैं या कर रहे हैं। इनमें मिलेनियल्स और जेनरेशन-जी जैसे वर्ग शामिल हैं। इन्होंने लोकतंत्र की परिभाषा विश्वविद्यालयों में सीखी है और उसके सिद्धांत तथा मूल्यों को पुस्तकों में पढ़ा है। ये सैद्धांतिक और व्यावहारिक लोकतंत्र में जो अंतर है, उसे देख सकते हैं, अंतर का विश्लेषण कर समाधान के विकल्प सोच सकते हैं। जो कुछ इस पीढ़ी ने देखा, सुना और समझा है, जो कुछ विद्वानों से सीखा या पुस्तकों में पढ़ा है, उसमें और लोकतंत्र के व्यावहारिक स्वरूप में विशाल अंतर इन्हें असमंजस में डाल रहा है।

इससे व्यग्रता जन्म लेती है, बढ़ती है और अनेक अवसरों पर वह उग्रता में परिवर्तित हो जाती है। श्रीलंका, बांग्लादेश और नेपाल की घटनाओं को इस संदर्भ में ही विश्लेषित किया जा रहा है। एक दूसरा वर्ग भी उन लोगों का है, जिनका जन्म परतंत्र भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की प्रजा के रूप में हुआ। वे स्वतंत्र भारत के नागरिक बने। इन्होंने देश के विभाजन तथा आबादी को 40 करोड़ से 140 करोड़ होते देखा एवं उससे जुड़े अन्य परिवर्तनों से भी भलीभांति प्रभावित हुए हैं। ये वे लोग हैं, जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन की खुशबू से परिचय पाया। इनकी अपेक्षाएं और आशाएं उस वातावरण में बढ़ रही थीं, जिसमें ऐसे अनेक व्यक्ति उपस्थित थे, जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपना सब कुछ न्योछावर कर दिया। उस पीढ़ी ने लोकतंत्र के जिस सैद्धांतिक लोकतंत्र से परिचय पाया था, उसी के अनुरूप सत्ता में पहुंचे लोगों को जीवन जीते देखा और आज उसको लगातार विरूपित होते भी देख रहे हैं। इनके समक्ष ज्यादा विचलित करने वाली स्थिति है या उन युवाओं के समक्ष, जिन्हें अपने भविष्य को जीना है, अपने लक्ष्य निर्धारित कर उन्हें प्राप्त करने के प्रयासों को प्रारंभ करना है।

20वीं सदी के उत्तरार्ध में जो देश प्रजातंत्र को अपना रहे थे, उनमें भारत में ही यह सबसे अधिक सफलतापूर्वक स्थापित हो सका है। भारत में प्राचीन परंपराओं और 'परहित' की सार्वभौमिक समझ के कारण ही लोकतंत्र व्यवस्थित ढंग से लागू हुआ और चलता रहा है, पर यह अत्यंत आश्चर्य का विषय है कि त्याग, तपस्या और जनसेवा के जो मूल्य गांधीजी और उनकी पीढ़ी के लोग सिखा गए, वे सब कहां खो गए। जैसे-जैसे चयनित प्रतिनिधियों को सत्ता में मिलने वाले अधिकार एवं सुविधाएं मिलीं, वे अपने निर्वाचकों को भूल गए और संपत्ति के संग्रहण में खो गए। पुलिस, कचहरी और स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता सामान्य व्यक्ति के लिए अत्यंत कष्टकर है।

हालांकि अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति के लिए पिछले कुछ वर्षों में सार्थक प्रयास किए गए हैं, ताकि उसका जीवन सुधरे और वह अपना जीवन सम्मान और मानवीय गरिमा के साथ जी सके, परंतु समस्या यह है कि यदि ऊपर से नीचे तक अधिकांश सरकारी कर्मचारी नैतिकता के मूल्यों से विलग हो चुके हों तो अच्छे से अच्छा प्रयास कागजों पर जो दर्शाता है, वह व्यावहारिकता में लगभग शून्य हो जाता है।

आखिर भारत जैसे देश में जहां मानव मूल दर्शन में 'सर्वभूतहिते रतः' (सभी प्राणियों के हित में लगे रहना) को अंगीकार किया गया हो, वहां नैतिकता बड़े स्तर पर तिरोहित होने के स्तर तक कैसे पहुंच गई है? क्या लोकतंत्र का अर्थ चुनाव जीतकर सत्ता में कोई पद पाना, अगले पांच वर्ष तक हर प्रकार से सपत्ति संग्रह करना और जनसेवा के स्थान पर अगला चुनाव जीतना मात्र रह गया है? चयनित प्रतिनिधियों ने अपने लिए सुविधाएं लगातार बढ़ाई हैं।

संभवतः अधिकांश यह भूल गए हैं कि इस देश में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी राजेंद्र प्रसाद, लालबहादुर शास्त्री, कर्पूरी ठाकुर, गुलजारी लाल नंदा, एपीजे अब्दुल कलाम जैसे अनेकानेक लोग हुए हैं, जो सत्ता में रहे, लेकिन केवल जनसेवा को ही जीवन लक्ष्य बनाया। अपना या अपने परिवार का सुख, संपत्ति और स्वजनों को आगे बढ़ाने का कोई प्रयास नहीं किया। पिछले दस वर्षों में भारत की वैश्विक साख सम्मानजनक स्तर पर पहुंच चुकी है, लेकिन नैतिकता और मूल्यों के ह्रास की प्रक्रिया रुकी नहीं है। भ्रष्ट नेताओं और नौकरशाहों के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं।

1962 और 1965 के युद्ध के समय सभी पंथों, जातियों, वर्गों के लोग हर प्रकार के अंतर और भेद को भुलाकर सरकार के साथ खड़े हुए। पक्ष-विपक्ष या राजनीतिक दल जैसा कोई भेदभाव नहीं था। 1971 में भी इंदिरा गांधी को विजय का श्रेय देने में पक्ष-विपक्ष पूरी तरह एक हो गया था। आज स्थिति यह है कि देश की सेना जो जानकारी देती है, उस पर विपक्ष प्रश्न पूछता है। अमेरिकी राष्ट्रपति जब अपनी सनक में कहते हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था मर चुकी है तो उसे विपक्ष के नेता तोता-रटंत करते हुए बिना अपने मस्तिष्क का उपयोग किए दोहरा देते हैं। कुछ तो ऐसे भी हैं, जो लगातार विदेश जाकर भारत की अस्वीकार्य आलोचना करते हैं, पाकिस्तान से देश के चयनित प्रधानमंत्री को हटाने में मदद मांगते हैं। देश के बुद्धिजीवियों, विद्वानों तथा राष्ट्र-समर्पित युवाओं को गहन विचार-विमर्श कर लोकतंत्र के मूलभूत सिद्धांतों को पुनर्स्थापित करने की पहल करनी चाहिए।

अभियान

शिव पुराण में वर्णित चमत्कारी पूजा विधि – जो कर दे हर इच्छा पूरी और दिलाए शिवलोक का आशीर्वाद

भगवान शिव का नाम लेते ही मन में एक गहन शांति और अद्भुत ऊर्जा का अनुभव होता है। त्रिलोकनाथ, महादेव, भोलेनाथ—इनके नाम ही कल्याणकारी हैं। किंतु शिव पुराण में वर्णित एक विशेष पूजा विधि ऐसी है, जो न केवल भक्त की समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करती है, बल्कि उसे सांसारिक दुःखों से मुक्त कर शिवस्वरूप बना देती है। इस विधि का उल्लेख स्वयं सूतजी ने किया था, जब ऋषियों ने उनसे पूछा कि महादेव की उपासना किस प्रकार की जाए जिससे वे प्रसन्न होकर भक्त को अपने कृपा-कटाक्ष से धन्य करें।

सूतजी ने कहा कि यह वही प्रश्न है जो कभी नारद जी ने ब्रह्माजी से किया था। तब ब्रह्माजी ने बताया था कि भगवान शिव की पूजा का मूल तत्व 'भक्ति' है, परंतु विधिवत पूजा करने से उसका प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। उन्होंने कहा कि बेलपत्र, कमलपत्र, शतपत्र और शंखपुष्प से शिवजी की पूजा करने से लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। पूजा में 20 कमल एक प्रस्थ के बराबर माने जाते हैं और सहस्र बेलपत्र आधे प्रस्थ के समान। जब इन्हें सच्चे मन से तौलकर अर्पित किया जाता है, तो भक्त के समस्त मनोरथ पूरे होते हैं। यदि यह पूजा निष्काम भाव से की जाए, तो वह भक्त स्वयं शिवस्वरूप हो जाता है।

सूतजी ने आगे कहा कि जो दस करोड़ पार्थिव लिंगों की पूजा करता है, उसे राजसुख और अपार वैभव की प्राप्ति होती है। शिवलिंग पर चावल, फूल, चंदन और अखंड जल की धारा चढ़ाना अत्यंत शुभ माना गया है। प्रत्येक मंत्र के साथ एक बेलपत्र, शतपत्र या कमल अर्पित करने से उस मंत्र का प्रभाव अनेक गुना बढ़ जाता है। शंखपुष्प से पूजा विशेष फलदायी होती है, जो भक्त को दोनों लोकों में सुख देती है। पूजा के बाद दीप, धूप, नैवेद्य, आरती और प्रदक्षिणा कर क्षमा प्रार्थना करनी चाहिए।

यह सांगोपांग पूजा न केवल भोग और राज्य प्रदान करती है, बल्कि रोग, शत्रु और भय से भी मुक्ति देती है। सूतजी ने विस्तार से बताया कि यदि कोई व्यक्ति रोगमुक्त होना चाहता है, तो उसे 50 कमल पुष्प से पूजा करनी चाहिए। कन्या की इच्छा रखने वाले को 25 हजार कमल पुष्प, विद्या की इच्छा वाले को आधे परिमाण से, वाणी के लिए घृत से, और राजा के वशीकरण हेतु 10 लाख पुष्पों से पूजन करना चाहिए। यश के लिए भी इतना ही, ज्ञान के लिए एक करोड़ और शिव-दर्शन के लिए उससे आधा पुष्प अर्पित करना श्रेष्ठ माना गया है।

शिवपुराण में यह भी कहा गया है कि जो व्यक्ति मुक्ति की कामना करता है, उसे कुशा से पूजा करनी चाहिए। आयु-वृद्धि के इच्छुक को एक लाख दूर्वा से, पुत्र की इच्छा रखने वाले को लाल डंडी वाले एक लाख पुष्पों से शिवजी का पूजन करना चाहिए। तुलसी से पूजा करने वाला भक्त भक्ति और मुक्ति दोनों प्राप्त करता है। प्रताप और वीरता के लिए आक के फूल अर्पित करने चाहिए। यदि कोई अपने शत्रुओं से मुक्ति चाहता है, तो उसे एक लाख पुष्प चढ़ाने चाहिए।

भगवान शिव को सभी फूल प्रिय हैं, केवल चंपा और केतकी के फूल वर्जित बताए गए हैं। शिवजी पर अखंडित चावल चढ़ाना अत्यंत शुभ होता है, जिससे लक्ष्मी की वृद्धि होती है। यदि भक्त एक लाख या छः प्रस्थ या दो पल चावल अर्पित करता है और उन पर गंध, श्रीफल तथा पुष्प रखकर धूप-दीप से पूजन करता है, तो उसे अनंत पुण्य प्राप्त होता है। इसके साथ यदि वह दो रुपया माशे की दक्षिणा दे और 12 ब्राह्मणों को भोजन कराए, तो पूजा पूर्ण मानी जाती है।

शिवपुराण में यह भी कहा गया है कि जो एक लाख पल तिल अर्पित करता है, उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। आठ प्रस्थ जौ अर्पित करने से स्वर्ग और सुख की वृद्धि होती है। जल की धारा से ज्वर और ग्रहदोष शांत होते हैं। एकादश रुद्र, शतरुद्रिय मंत्र, महामृत्युञ्जय जाप, या रुद्र सूक्त के साथ जलाभिषेक करने से समस्त दुःख दूर होते हैं। यदि किसी घर में कलह और क्लेश हो, तो प्रतिदिन शिवलिंग पर जल की धारा चढ़ाने से वातावरण शांत होता है। सूतजी ने कहा कि शत्रु को शमन करने के लिए तेल से, यक्षराज बनने के लिए शहद से, और आनंद व समृद्धि के लिए गन्ने के रस से अभिषेक करना चाहिए। गंगा जल से पूजा करने से भक्ति और मुक्ति दोनों की प्राप्ति होती है। दस हजार गंगाजल की धाराओं का विधान कहा गया है, और अंत में 11 ब्राह्मणों को भोजन कराने से यह अनुष्ठान पूर्ण होता है।

अंत में सूतजी ने कहा – "हे मुनिवरों! जो भक्त स्कंद और उमा सहित भगवान शिव की सविधि पूजा करता है, वह पुत्र-पौत्र, यश, धन, सुख, ज्ञान और मोक्ष सब प्राप्त करता है। वह इस लोक में सभी सुखों का भोग करता हुआ अंततः महेश्वर लोक का भागी बनता है।"

इस प्रकार शिवपुराण में वर्णित यह पूजन विधि न केवल भक्त की इच्छाओं को पूर्ण करती है, बल्कि उसके जीवन को पवित्रता, भक्ति और शांति से भर देती है। जो भी व्यक्ति सच्चे मन से इन विधियों का पालन करता है, उसके जीवन में कोई कार्य असंभव नहीं रहता, क्योंकि शिव कृपा से ही संसार के समस्त द्वार खुल जाते हैं।

RNI No. GUJHIN/2011/39228 Printed, Published & Owned by AJAYKUMAR RAMANLAL PRAJAPATI and Printed By (1) JIGNESH RASHIKBHAI GAJJAR at Vansh Corporation, A/8, Shayona Golden Estate, Shahibag, Ahmedabad - 380 004
(2) DESAI RAHUL MAHESHBHAI at Bhavani Offset, Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmedabad-380 002. (3) HADIK MAHESHBHAI DESAI at Bhoomi Offset, Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmedabad-380 002
and Published from TF-01, Nanakram Super Market, Ramnagar, Sabarmati, Ahmedabad - 380 005. Editor : MANOJKUMAR CHAMPAKLAL SHAH

चुनावी अनुशासन पर जद(यू) की बड़ी कार्रवाई, पूर्व मंत्री समेत 16 नेता पार्टी से निष्कासित

पटना। बिहार में विधानसभा चुनाव का माहौल गरमाने के साथ ही जनता दल (यूनाइटेड) ने पार्टी के भीतर अनुशासन कायम करने के लिए बड़ा कदम उठाया है। पार्टी ने शनिवार और रविवार को मिलाकर कुल 16 नेताओं को पार्टी विरोधी गतिविधियों और विचारधारा की अवहेलना के आरोप में निष्कासित कर दिया। इस सूची में पूर्व मंत्री, कई पूर्व विधायक और पूर्व विधान पार्षद शामिल हैं।

जद(यू) की प्रदेश इकाई के महासचिव चंदन कुमार सिंह ने बयान जारी करते हुए कहा कि इन सभी नेताओं को पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से निलंबित किया गया है। उन्होंने कहा, "पार्टी ने पाया कि ये नेता लगातार संगठन के खिलाफ काम कर रहे हैं और राजग के अधिकृत प्रत्याशियों के विरोध में सक्रिय हैं। ऐसे में अनुशासनात्मक कार्रवाई करना आवश्यक था।"

शनिवार को जारी पहली सूची में पूर्व मंत्री शैलेश कुमार, पूर्व विधायक श्याम बहादुर सिंह, सुधर्शन कुमार, पूर्व विधान पार्षद संजय प्रसाद और रणविजय सिंह समेत 11 नेताओं को निष्कासित किया गया था। रविवार को पार्टी ने दूसरी सूची जारी करते हुए विधायक गोपाल मंडल, पूर्व विधायक महेश्वर यादव, पूर्व एमएलसी संजिव श्याम सिंह सहित पांच अन्य नेताओं को भी बाहर का रास्ता दिखा दिया।

पार्टी सूत्रों का कहना है कि ये सभी नेता गठबंधन के अधिकृत उम्मीदवारों के खिलाफ चुनाव प्रचार में लगे हुए थे, जिससे संगठन की एकजुटता पर असर पड़ रहा था। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और पार्टी नेतृत्व ने साफ संदेश दिया है कि जो भी नेता अनुशासन तोड़ेगा या गठबंधन के खिलाफ काम करेगा, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

बिहार में इस बार 243 सीटों वाली विधानसभा के लिए चुनाव दो चरणों में होंगे — पहले चरण का मतदान 6 नवंबर को और दूसरे चरण का 11 नवंबर को होगा। 14 नवंबर को नतीजे घोषित किए जाएंगे। इस बार का चुनाव राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) और महागठबंधन के बीच मुख्य मुकाबले के रूप में देखा जा रहा है, हालांकि प्रशांत किशोर की नई पार्टी जनसुराज के मैदान में उतरने से सियासी समीकरण और दिलचस्प हो गए हैं।

जद(यू) की इस सख्त कार्रवाई ने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है। विशेषज्ञों का मानना है कि चुनावी मौसम में पार्टी द्वारा बागी नेताओं पर गाज गिराना एक रणनीतिक कदम है, जिससे संगठन में अनुशासन बना रहे और जनता के बीच यह संदेश जाए कि नीतीश कुमार की पार्टी किसी भी सूरत में अंदरूनी असंतोष को सहन नहीं करेगी। पार्टी के भीतर अब यह माना जा रहा है कि यह कदम न केवल संगठनात्मक अनुशासन को मजबूत करेगा बल्कि राजग के भीतर समन्वय को भी सुदृढ़ करेगा। जद(यू) ने साफ कर दिया है कि आगामी विधानसभा चुनाव में केवल वही नेता साथ चलेंगे जो पार्टी की नीति और विचारधारा के प्रति वफादार हैं।

गुजरात में 804 करोड़ की साइबर ठगी का पर्दाफाश, दुबई-कंबोडिया से चल रहा था नेटवर्क

गांधीनगर। गुजरात पुलिस ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर फैले एक विशाल साइबर अपराध सिंडिकेट का खुलासा किया है, जिसने देशभर में नागरिकों से लगभग 804 करोड़ रुपये की ठगी की है। राज्य के गृह मंत्री हर्ष संघवी ने मंगलवार को बताया कि इस गिरोह का संचालन दुबई, वियतनाम और कंबोडिया से किया जा रहा था, और भारत के सैकड़ों शहरों में इसके एजेंट सक्रिय थे।

इस हाईटेक ठगी के तार गुजरात के सूरत से जुड़े हैं, जहां से पुलिस ने 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरोह का मुख्य तरीका था आम लोगों को झांसा देकर उनके बैंक अकाउंट और सिम कार्ड हासिल करना। गिरोह अपने शिकारों को 1.5 से 2 प्रतिशत कमीशन का लालच देता था और उनके खातों का इस्तेमाल करोड़ों की अवैध ऑनलाइन लेनदेन के लिए करता था।

गृह मंत्री संघवी ने बताया कि इस नेटवर्क ने पूरे देश में अब तक 1,549 साइबर अपराधों को अंजाम दिया, जिनमें गुजरात में अकेले 141 मामले दर्ज हुए हैं। राज्य में इन अपराधों के जरिए करीब 17.75 करोड़ रुपये की ठगी की गई, जबकि कुल देशव्यापी ठगी की राशि 804 करोड़ रुपये तक पहुंच गई है।

पुलिस ने सूरत में छापेमारी के दौरान गिरोह के पास से भारी मात्रा में डिजिटल और बैंकिंग उपकरण बरामद किए हैं, जिनमें शामिल हैं — 65 मोबाइल फोन, 447 डेबिट कार्ड, 529 बैंक अकाउंट किट, 686 सिम कार्ड और 16 पीओएस मशीनें। ये सभी उपकरण ठगी के नेटवर्क को संचालित करने के लिए उपयोग में लाए जा रहे थे।

हर्ष संघवी ने बताया कि राज्य पुलिस ने अब तक की जांच में कुछ पीड़ितों को 5.51 करोड़ रुपये की राशि वापस लौटाई है और शेष रकम को ट्रेस करने की प्रक्रिया जारी है। उन्होंने कहा कि पुलिस ने इस प्रकार के साइबर अपराधों के खिलाफ "युद्धस्तर की कार्रवाई" शुरू कर दी है और अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों के साथ समन्वय भी बढ़ाया जा रहा है।विशेषज्ञों के मुताबिक, यह अब तक का सबसे बड़ा संगठित साइबर फ्रॉड नेटवर्क हो सकता है, जिसने भारतीय नागरिकों के केवाईसी डेटा, बैंक अकाउंट और डिजिटल पहचान का दुरुपयोग किया। पुलिस साइबर फॉरेंसिक और बैंकिंग इंटेलिजेंस टीमों की मदद से अब गिरोह के विदेशी संपर्कों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। राज्य सरकार ने लोगों से अपील की है कि वे किसी भी संदिग्ध ऑनलाइन ऑफर, निवेश योजना या 'कमीशन पर अकाउंट इस्तेमाल' जैसे प्रलोभनों से दूर रहें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की तुरंत पुलिस या साइबर हेल्पलाइन 1930 पर शिकायत करें। यह मामला न केवल गुजरात, बल्कि पूरे देश के लिए चेतावनी है कि डिजिटल अर्थव्यवस्था के युग में सुरक्षा जागरूकता और सतर्कता ही सबसे बड़ा बचाव है।

हिमाचल में जलवायु संकट की चेतावनी: चार साल में 46,000 करोड़ का नुकसान और 1,700 जानें गईं

शिमला। हिमालय की गोद में बसे हिमाचल प्रदेश पर जलवायु परिवर्तन की मार लगातार गहराती जा रही है। कभी बर्फ से ढकी शांत वादियां और कल-कल बहती नदियां अब विनाशकारी प्राकृतिक आपदाओं की गवाह बन रही हैं। राज्य सरकार की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार, पिछले चार वर्षों में जलवायु असंतुलन और प्राकृतिक आपदाओं के चलते हिमाचल प्रदेश को लगभग 46,000 करोड़ रुपये का आर्थिक नुकसान हुआ है, जबकि 1,700 से अधिक लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है।

यह खुलासा सोमवार को जारी की गई 'हिमाचल प्रदेश मानव विकास रिपोर्ट 2025: जलवायु प्रभावित विश्व में भविष्य का निर्माण' में किया गया है, जिसे राज्य के पर्यावरण एवं विज्ञान विभाग ने संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP) के सहयोग से तैयार किया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने रिपोर्ट जारी करते हुए कहा कि यह आंकड़े केवल आर्थिक हानि का नहीं, बल्कि पर्यावरणीय असंतुलन की गहराती त्रासदी का प्रतीक हैं।

रिपोर्ट में बताया गया है कि पिछले पांच मानसून सीज़नों में प्रदेश ने अभूतपूर्व तबाही देखी है। अनियमित और अत्यधिक वर्षा ने न केवल पहाड़ी ढलानों को अस्थिर किया है, बल्कि भूस्खलन और बादल फटने जैसी घटनाएं आम होती जा रही हैं। नतीजा यह हुआ कि राज्य के लगभग 70 प्रतिशत पारंपरिक जल स्रोत या तो पूरी तरह सूख चुके हैं या सूखने की कगार पर हैं। इसका सीधा असर ग्रामीण जीवन पर पड़ा है — कई इलाकों में पीने के पानी की भारी कमी और खेती पर संकट के कारण पलायन बढ़ता जा रहा है।

सिर्फ पानी ही नहीं, आग भी अब हिमाचल की नई चुनौती बन गई है। रिपोर्ट बताती है कि जंगलों में आग लगने की घटनाओं में खतरनाक बढ़ोतरी हुई है — वर्ष 2022-23 में जहां 856 मामले दर्ज किए गए थे, वहीं 2024-25 में यह आंकड़ा बढ़कर 2,580 तक पहुंच गया है। यह तीन गुना वृद्धि राज्य के पारिस्थितिकी तंत्र और वन्यजीवों के लिए भयावह संकेत है। विशेषज्ञों के अनुसार, बढ़ते तापमान, सूखे हालात और वन प्रबंधन में लापरवाही इस संकट को और जटिल बना रहे हैं।

मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि अब समय आ गया है जब सरकार और समाज दोनों को जलवायु संकट को केवल पर्यावरणीय नहीं, बल्कि विकास के केंद्र में रखकर सोचना होगा। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार आपदा प्रबंधन को मजबूत करने, जल संरक्षण के पारंपरिक तरीकों को पुनर्जीवित करने और हरित अर्थव्यवस्था की दिशा में ठोस कदम उठाने जा रही है।

रिपोर्ट चेतावनी देती है कि यदि आने वाले वर्षों में कारगर कदम नहीं उठाए गए, तो हिमाचल की प्राकृतिक, सामाजिक और आर्थिक संरचना पर स्थायी असर पड़ सकता है। जलवायु परिवर्तन से प्रभावित पहाड़ी पारिस्थितिकी तंत्र केवल हिमाचल की नहीं, बल्कि पूरे उत्तर भारत की जल सुरक्षा के लिए खतरा है, क्योंकि यही नदियों का उद्गम स्थल है। हिमाचल की यह त्रासदी केवल एक राज्य की कहानी नहीं, बल्कि उस वैश्विक संकट की गूंज है, जो हर पहाड़, हर नदी और हर गाँव में धीरे-धीरे दस्तक दे रही है। सवाल अब यह है कि क्या हम आने वाली पीढ़ियों के लिए हिमालय को उसी रूप में बचा पाएंगे, जैसा हमने अपने पूर्वजों से पाया था — या फिर यह हिमालय भी हमारी उपेक्षा की आग में पिघल जाएगा।

छोटी उम्र में मेकअप आपकी बच्ची को नुकसान पहुंचा सकता है -शहनाज़ हुसैन

कहावत है कि बेटियां कब बड़ी हो जाती हैं, पता ही नहीं चलता/ मगर आजकल यह कहावत कुछ ज्यादा ही पहले चरितार्थ होने लगी है।

कभी मां की देखादेखी तो कभी बस शौक के चलते बच्चियों में मेकअप का रुझान तेजी से बढ़ रहा है।

ज्यादातर घरों में बच्चे जब अपने घर की महिलाओं , मम्मी, दीदी, मौसी, बुआ और चाची को मेकअप करते देखते हैं जो वह भी मेकअप करने की जिद करने लगते हैं जिससे अधिकतर पेरेंट्स बिना ना.नुकुर किए अपने बच्चों का मेकअप करने लग जाते हैं और कुछ मामलों में उन्हें मेकअप के लिए प्रोत्साहित भी करते हैं।

कम उम्र में ही इन बच्चियों का ध्यान रचनात्मक अभिव्यक्ति से हटकर शारीरिक दिखावे पर केंद्रित होने लगता है। सोशल मीडिया प्लेटफार्म जैसे ट्विटर ,इंस्टाग्रामए फेसबुक आदि पर युवा इन्फ्लुएंसर के रूप में मेकअप को प्रमोट करती बच्चियों के फालोअर्स की लंबी फेहरिस्त सामान्य बच्चियों को भी इस ओर आकर्षित करती है।

मेकअप असल में कम उम्र में ही बच्चियों को शारीरिक और मानसिक तौर पर नुकसान पंहुचा रहा है।

बच्चों की त्वचा बहुत नाजुक होती है और सौन्दर्य प्रसाधनों में मौजूद केमिकल्स की बजह से बच्चियों में हार्मोन संतुलन बिगड़ जाता है।

सौन्दर्य प्रसाधनों में रेटिनॉइड्स ,ग्लाइकोलिक एसिड जैसे तत्व विद्यमान होते हैं जोकि बच्चियों की नाजुक त्वचा के बैरियर को नुकसान करते हैं ,

जिसकी बजह से त्वचा में रूखापन एलर्जी, जलन और कील ,मुहांसों जैसी समस्याएं हो सकती/

बच्चियों की नाजुक त्वचा में जबां महिलाओं की तुलना में कमजोर और पतले स्किन बैरियर्स होते हैं जिसकी बजह से सौन्दर्य प्रसाधनों में विद्यमान रासायनिक पदार्थ त्वचा के भीतरी हिस्सों तक पहुंच जाते हैं और इससे त्वचा को दीर्धकालीन नुकसान पहुंचता है।

कम उम्र में अगर आपकी बच्ची होठों पर लिपस्टिक लगाती है तो इससे होंठ से पपड़ी निकलना और कालापन दिखना भी शुरू हो सकता है।

कुछ लिपस्टिक सौन्दर्य प्रसाधनों को लचीला बनाने और सुगन्धित रखने के लिए जिन पैराबेन्स, फ़थैलेट्स और फिनोल पदार्थों का उपयोग किया जाता है उनके नियमित उपयोग से बच्चियों में समय से पूर्व प्यूबर्टी की शुरुआत हो जाती है तथा इनके लम्बे समय से उपयोग से स्तन और ओवेरीअन कैंसर तक का खतरा बढ़ जाता है।

कई बार केमिकल युक्त सौन्दर्य प्रसाधनों के उपयोग से त्वचा का प्रकृतिक पी एच और माइक्रोब्स संतुलन बिगड़ जाता है जिससे एक्जिमा का संक्रमण हो सकता है। अगर छोटी बच्चियों में एक्जिमा का संक्रमण हो जाये तो इन सौन्दर्य उत्पादों के सेवन से तत्काल रोक दीजिए और इससे काफी हद तक राहत मिल जाएगी।

पर्सनल केयर उत्पादों में जिस सुगन्धित और प्रिजर्वेटिव उत्पादों का उपयोग किया जाता है बह भी बच्चियों में एलर्जी का मुख्य कारण बन जाती है

सोशल मीडिया के प्रभाव में आ कर बच्चियां सुन्दरता के नए मापदण्डों के अनुरूप ब्यूटी स्टैण्डर्ड तय कर लेती हैं जिन्हें पाना काफी मुश्किल होता है

और इसकी बजह से बह मानसिक तनाव में आ जाती हैं जिसका असर उनकी शारीरिक और मानसिक विकास पर पड़ता है। इसकी बजह से कई बार बह डिप्रेशन, उत्तेजना और बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर का शिकार हो जाती हैं। मगर बच्ची में इसके प्रति समझ व सहनशीलता विकसित नहीं होती, जिससे वह मानसिक तौर पर परेशान होने लगती है।

मुझे लगता है की पेरेंट्स को युवा बच्चों को स्किन केयर वीडियो से परहेज करने के लिए एक्टिव रोल प्ले करना चाहिए और इसके लिए उन्हें इन उत्पादों के नुकसान के बारे में ब्यबहारिक और बिस्तृत जानकारी देनी चाहिए जोकि बच्चों के मस्तिक पटल पर घर कर जाये।

छठ महापर्व का भव्य समापन: उगते सूर्य को अर्घ्य के साथ देशभर में गूंजी आस्था, प्रधानमंत्री मोदी ने दी शुभकामनाएं

नई दिल्ली। उगते सूर्य को अर्घ्य अर्पित कर चार दिवसीय छठ महापर्व का आज विधिवत समापन हुआ। देश के कोने-कोने में सुबह से ही श्रद्धालु घाटों और जलाशयों पर जुटे, जहां मंत्रोच्चार, भजनों और आस्था की अद्भुत छटा ने वातावरण को आध्यात्मिक बना दिया। यह पर्व न केवल धार्मिक श्रद्धा का प्रतीक है, बल्कि सामाजिक एकता और पारिवारिक सौहार्द की भावना का उत्सव भी है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि भगवान सूर्यदेव को प्रातःकालीन अर्घ्य के साथ छठ महापर्व का पावन समापन हुआ। उन्होंने कहा कि चार दिनों तक चले इस अनुष्ठान में श्रद्धा, अनुशासन और भक्ति का अनोखा संगम देखने को मिला। प्रधानमंत्री ने सभी व्रती महिलाओं, श्रद्धालुओं और आयोजन में सहभागी परिवारों को हृदय से नमन करते हुए कामना की कि छठी मइया की असीम कृपा सबके जीवन को सदैव प्रकाशमान बनाए रखे।

सूर्योदय से पहले ही घाटों पर अपार जनसैलाब उमड़ पड़ा। बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, झारखंड, दिल्ली, मुंबई, चंडीगढ़ और मध्य प्रदेश के कई शहरों में गंगा, यमुना और अन्य नदियों के तटों पर लाखों श्रद्धालु इस महान पर्व की अंतिम विधि में शामिल हुए। वाराणसी, पटना और भागलपुर के घाटों पर तो भोर होते ही भक्तों का सागर उमड़ आया। सूर्यदेव को अर्घ्य देते समय ढोल-मंजीरे की धुन और 'जय छठी मइया' के जयकारों से पूरा वातावरण गुंजायमान हो उठा।

दिल्ली के यमुना घाटों से लेकर मुंबई के समुद्री किनारों तक श्रद्धा का वही रंग दिखाई दिया। महिलाओं ने पारंपरिक वेशभूषा में सिर पर पूजा का सूप लिए जल में खड़े होकर सूर्यदेव और छठी मइया से परिवार की सुख-समृद्धि और आरोग्य की कामना की। कठोर व्रत और आत्मसंयम से भरा यह पर्व स्त्री-शक्ति, निष्ठा और मातृत्व के गौरव का जीवंत प्रतीक माना जाता है। पूरे आयोजन के दौरान प्रशासन ने सुरक्षा और स्वच्छता की व्यापक व्यवस्था की थी। कई शहरों में पुलिस बलों की तैनाती, ड्रोन निगरानी और मेडिकल सहायता केंद्रों की व्यवस्था रखी गई थी ताकि कोई अप्रिय घटना न हो। नदी और तालाबों के किनारे सफाई कर्मियों ने लगातार काम करते हुए श्रद्धालुओं को स्वच्छ वातावरण उपलब्ध कराया।

यह पर्व 25 अक्टूबर को 'नहाय-खाय' से आरंभ हुआ था। दूसरे दिन 'खरना' की पूजा के साथ व्रतियों ने उपवास प्रारंभ किया, तीसरे दिन संध्या अर्घ्य और आज उषा अर्घ्य के साथ व्रत का समापन हुआ। इस दौरान व्रती महिलाएं बिना जल ग्रहण किए दिन-रात पूजा-अर्चना में लीन रहीं। लोक परंपरा के अनुसार छठी मइया सूर्यदेव की बहन हैं और वह संतान की दीर्घायु तथा परिवार की समृद्धि का वरदान देती हैं।

देश के बाहर भी इस पर्व की झलक देखने को मिली। अमेरिका, ब्रिटेन, दुबई, नेपाल और मॉरीशस में बसे भारतीयों ने पारंपरिक गीतों और विधियों के साथ छठ मनाया। सोशल मीडिया प्लेटफार्मों पर घाटों की तस्वीरें और वीडियो वायरल होते रहे, जिसने इस प्राचीन भारतीय आस्था को वैश्विक पहचान दिलाने का कार्य किया। छठ सिर्फ पूजा नहीं, बल्कि सूर्य और प्रकृति के प्रति मानव की कृतज्ञता का उत्सव है — एक ऐसा पर्व जो हर वर्ष यह स्मरण कराता है कि जीवन का वास्तविक प्रकाश श्रद्धा, शुचिता और अनुशासन में ही निहित है।

भावनगर रेलवे मंडल के कर्मचारियों ने यात्री का भूलवश छूटा लैपटॉप सुरक्षित लौटाया

पश्चिम रेलवे, भावनगर मंडल के कर्मचारी अपने सम्मानित यात्रियों की सहायता हेतु सदैव तत्पर रहते हैं। इसी प्रतिबद्धता का एक उत्कृष्ट उदाहरण वेरावल स्टेशन पर देखने को मिला, जहाँ एक यात्री का लैपटॉप वाला बैग भूलवश छूट गया था, जिसे रेलवे कर्मचारियों ने अत्यंत ईमानदारी एवं जिम्मेदारी के साथ सुरक्षित रखकर यात्री को लौटा दिया।

वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक श्री अतुल कुमार त्रिपाठी ने बताया कि लगभग एक सप्ताह पूर्व वेरावल स्टेशन पर एक लावारिश बैग एक रेलवे कर्मचारी को मिला था। कर्मचारी द्वारा सतर्कता दिखाते हुए बैग को स्टेशन अधीक्षक कार्यालय में जमा कराया गया। जांच के दौरान बैग में एक लैपटॉप मिला। बैग की गहन जांच करने पर एक संपर्क नंबर प्राप्त हुआ, जिस पर संपर्क करने पर यात्री ने अपनी भूल स्वीकार की और रेलवे प्रशासन को धन्यवाद दिया।

यात्री, जो राजस्थान के निवासी हैं, ने वापसी पर बैग प्राप्त करने का अनुरोध किया तथा रेलवे से उसे सुरक्षित रखने का आग्रह किया। यात्री की सुविधा को ध्यान में रखते हुए, बैग को स्टेशन पर सुरक्षित रूप से रखा गया। दिनांक 28 अक्टूबर, 2025 (मंगलवार) को संबंधित यात्री के वेरावल स्टेशन पर आगमन के पश्चात आवश्यक सत्यापन और पूछताछ के बाद लैपटॉप युक्त बैग उन्हें लौटा दिया गया।

लैपटॉप सुरक्षित रूप से प्राप्त होने पर यात्री ने रेलवे प्रशासन के प्रति गहरी कृतज्ञता व्यक्त की और सभी संबंधित कर्मचारियों का धन्यवाद किया।

मंडल रेल प्रबंधक श्री दिनेश वर्मा ने इस सराहनीय कार्य के लिए संबंधित कर्मचारियों की प्रशंसा करते हुए उन्हें प्रोत्साहित किया और कहा कि यह कार्य भारतीय रेल की ईमानदारी, जिम्मेदारी एवं यात्री सेवा की भावना का प्रतीक है।

मानसिक रोगियों की गरिमा पर सुप्रीम कोर्ट सख्त: "जंजीरों में बांधना असंवैधानिक", निगरानी की जिम्मेदारी NHRC को सौंपी

नई दिल्ली। देश में मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी व्यवस्था और उसके मानवीय पक्ष को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक टिप्पणी की है। अदालत ने साफ कहा है कि मानसिक रोगियों को जंजीरों में बांधना न सिर्फ क्रूर और अमानवीय है, बल्कि यह संविधान के अनुच्छेद 21 — यानी गरिमा के साथ जीवन के मौलिक अधिकार — का खुला उल्लंघन है। अदालत ने इस संबंध में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए मामले की पूरी निगरानी की जिम्मेदारी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) को सौंप दी है। अब आयोग यह सुनिश्चित करेगा कि देशभर में मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम, 2017 का सही ढंग से पालन हो और मानसिक रोगियों के साथ किसी भी प्रकार का अमानवीय व्यवहार न किया जाए।

यह जनहित याचिका अधिवक्ता गौरव कुमार बंसल ने 2018 में दायर की थी। याचिका में दावा किया गया था कि देश के कई राज्यों में मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम के अहम प्रावधानों को लागू नहीं किया जा रहा, जिससे मरीजों के मानवाधिकारों का लगातार हनन हो रहा है। विशेष रूप से उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले के एक धार्मिक आश्रम में मानसिक रोगियों को जंजीरों से बांधे जाने की घटना का हवाला देते हुए कहा गया था कि इस तरह का व्यवहार किसी भी सभ्य समाज में अस्वीकार्य है।

न्यायमूर्ति पी.एस. नरसिम्हा और न्यायमूर्ति आर. महादेवन की खंडपीठ ने सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार से पूछा कि मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम को जमीनी स्तर पर कैसे लागू किया जा रहा है। केंद्र की ओर से दायर हलफनामे में बताया गया कि देशभर में केंद्रीय मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण (CMHA), राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण (SMHA) और मानसिक स्वास्थ्य समीक्षा बोर्ड (MHRB) का गठन हो चुका है। अदालत ने इन संस्थाओं के कामकाज की निगरानी और मूल्यांकन का कार्य NHRC को सौंपते हुए कहा कि आयोग समय-समय पर अपनी रिपोर्ट अदालत को सौंपे और यह सुनिश्चित करे कि मरीजों के अधिकारों की रक्षा हो।

सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि मानसिक बीमारी किसी अपराध की तरह नहीं देखी जा सकती। इस स्थिति में जी रहे व्यक्ति को सहानुभूति, चिकित्सा और सम्मान की आवश्यकता होती है, न कि बेड़ियों और अपमान की। अदालत ने राज्यों को भी निर्देश दिया कि वे अपने-अपने इलाकों में निजी और सरकारी मानसिक स्वास्थ्य संस्थानों की स्थिति की समीक्षा करें, यह सुनिश्चित करें कि वहां किसी भी मरीज को बंदी बनाकर या हिंसक तरीके से नहीं रखा जा रहा है। 2017 में बने मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम का मकसद मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं को एक अधिकार-आधारित प्रणाली में शामिल करना था, ताकि किसी व्यक्ति की बीमारी उसकी गरिमा और स्वतंत्रता को छीन न सके। इस अधिनियम के तहत मरीज को इलाज का अधिकार, अपनी सहमति से उपचार का विकल्प चुनने का अधिकार और संस्थागत देखभाल में मानवीय व्यवहार का अधिकार सुनिश्चित किया गया है। सुप्रीम कोर्ट के इस कदम ने मानसिक स्वास्थ्य को लेकर समाज और शासन दोनों के लिए एक गहरी चेतावनी दी है।

पश्चिम रेलवे - अहमदाबाद

ईपीसी-निविदा सूचना संख्या DyCECIIADIJND-Re-D-EPC-R1

जूनागढ़ जंक्शन रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास

पश्चिम रेलवे, अहमदाबाद के उप-मुख्य अभियंता (निर्माण) II, भारत संघ के राष्ट्रपति की ओर से, निम्नलिखित कार्य के लिए खुली निविदा आमंत्रित करते हैं:

कार्य का नाम और स्थान: पश्चिम रेलवे के भावनगर मंडल के जूनागढ़ जंक्शन रेलवे स्टेशन का इंजीनियरिंग, खरीद और निर्माण (ईपीसी) [सिंगल स्टेज] मोड पर पुनर्विकास।

कार्य की अनुमानित लागत: ₹81,56,43,806.00 (केवल इक्यासी करोड़ छप्पन लाख तैंतालीस हजार आठ सौ छह रुपये)

ऑनलाइन गेटवे के माध्यम से जमा की जाने वाली बयाना राशि: रु. 40,78,300.00 (केवल चालीस लाख अट्ठहत्तर हज़ार तीन सौ रुपये)

पूर्णता अवधि: 24 (चौबीस) महीने

बोली-पूर्व बैठक: 31-10-2025 को 12:00 बजे

बोली जमा करने की तिथि और समय तकनीकी बोली खोलना: 19-11-2025 को 15:00 बजे तक जमा करना।

निविदा खोलने की तिथि: 19-11-2025 को 15:30 बजे

निविदा बोली प्रणाली: दो पैकेट प्रणाली। ईपीसी (सिंगल स्टेज)।

वेबसाइट विवरण, सूचना पट्ट का स्थान जहाँ निविदा का पूरा विवरण देखा जा सकता है और कार्यालय का पता: उप मुख्य अभियंता (निर्माण) II का कार्यालय, पश्चिम रेलवे, द्वितीय तल, निर्माण भवन, मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय के पास, असरवा, अहमदाबाद।

वेबसाइट: www.ireps.gov.in

CPM 073

हमें लाइक करें: facebook.com/WesternRly • हमें फॉलो करें: twitter.com/WesternRly

चक्रवाती तूफान 'मोंथा' का कहर: 110 किमी प्रतिघंटा की रफ्तार, 4.7 मीटर ऊंची लहरों से कांपे तटीय राज्य

हैदराबाद/भुवनेश्वर/चेन्नई। बंगाल की खाड़ी में बना चक्रवाती तूफान 'मोंथा' अब गंभीर रूप धारण कर चुका है और तेजी से आंध्र प्रदेश के काकीनाडा तट की ओर बढ़ रहा है। मौसम विभाग के अनुसार, यह तूफान सोमवार देर रात तक तट को पार कर सकता है। तूफान के दौरान हवा की रफ्तार 90 से 110 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंचने की संभावना है, जबकि समुद्र में 4.7 मीटर तक ऊंची लहरें उठने लगी हैं। इसके चलते आंध्र प्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और पुडुचेरी में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है।

काकीनाडा बंदरगाह और आसपास के तटीय जिलों में सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर हैं। विशाखापत्तनम चक्रवात चेतावनी केंद्र ने चेतावनी जारी करते हुए कहा कि समुद्र में किसी भी प्रकार की गतिविधि पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी। काकीनाडा के अलावा विशाखापत्तनम, गंगावरम और मछलीपट्टनम बंदरगाहों पर भी विशेष सतर्कता बरती जा रही है। मोंथा के खतरे को देखते हुए रेलवे ने 100 से अधिक ट्रेनों को रद्द कर दिया है, जबकि कई उड़ानें भी स्थगित कर दी गई हैं। तटीय इलाकों से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। प्रशासन ने एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें प्रभावित जिलों में तैनात कर दी हैं। समुद्र के किनारे बसे गांवों से हजारों लोगों को राहत शिविरों में शिफ्ट किया गया है।

आंध्र प्रदेश आपदा प्रबंधन विभाग के प्रबंध निदेशक प्रखर जैन ने बताया कि तूफान का 'लैंडफॉल प्रोसेस' शुरू हो चुका है और अगले कुछ घंटों में यह गंभीर चक्रवाती तूफान में तब्दील हो सकता है। उन्होंने लोगों से घरों में रहने और प्रशासन द्वारा जारी निर्देशों का पालन करने की अपील की।

वर्तमान में चक्रवात मोंथा बंगाल की खाड़ी के पश्चिम-मध्य भाग में स्थित है। चक्रवात चेतावनी केंद्र के ड्यूटी ऑफिसर जगन्नाथ कुमार ने बताया कि यह काकीनाडा से लगभग 240 किमी दक्षिण-दक्षिणपूर्व, मछलीपट्टनम से 160 किमी दक्षिण-दक्षिणपूर्व और ओडिशा के गोपालपुर से 530 किमी दक्षिण-दक्षिण पश्चिम में है। अनुमान है कि यह तूफान सोमवार रात तक काकीनाडा के

आसपास के तट को पार करेगा।

आंध्र प्रदेश के कई तटीय जिलों—चित्तूर, काकीनाडा, एनटीआर और आसपास के क्षेत्रों में मौसम का असर दिखने लगा है। कुशस्थली नदी में बाढ़ आने से सड़क संपर्क बाधित हो गया है। उप्पदा तट पर समुद्र की लहरें लगातार किनारों को काट रही हैं। बिजली विभाग को संभावित नुकसान के मद्देनजर सतर्क मोड पर रखा गया है। मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू राहत कार्यों की निगरानी स्वयं कर रहे हैं। राज्य सरकार ने 24 ड्रोन की मदद से रियल टाइम निगरानी शुरू की है, जबकि राहत शिविरों में रह रहे लोगों को भोजन, पेयजल और 3,000 की नकद सहायता दी जा रही है।

भारतीय मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि अगले कुछ दिनों में रायलसीमा, तमिलनाडु, तेलंगाना, ओडिशा, कर्नाटक और छत्तीसगढ़ में भारी वर्षा हो सकती है। आंध्र प्रदेश में 27 से 31 अक्टूबर तक और ओडिशा में 28 व 29 अक्टूबर को स्कूल-कॉलेज बंद रखने के आदेश जारी किए गए हैं। पश्चिम बंगाल में भी मोंथा का असर दिखने लगा है। मौसम विभाग ने कहा है कि मंगलवार से शुक्रवार तक दार्जिलिंग, कलिम्पोंग और दक्षिण बंगाल के जिलों में भारी बारिश हो सकती है। भूस्खलन और जलभराव की आशंका के चलते प्रशासन ने राहत दलों को तैनात कर दिया है।

ओडिशा सरकार ने भी मलकानगिरी, कोरापुट, नबरंगपुर, रायगढ़ा, गजपति, गंजाम, कंधमाल और कालाहांडी जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। राज्य में कुल 128 आपदा प्रतिक्रिया दल सक्रिय कर दिए गए हैं।

रेलवे और परिवहन व्यवस्था पर भी तूफान का गहरा असर पड़ा है। साउथ सेंट्रल रेलवे ने 28 और 29 अक्टूबर की 72 ट्रेनों को रद्द किया है, जबकि ईस्ट कोस्ट रेलवे पहले ही 43 ट्रेनों को स्थगित कर चुका है। पटरियों, पुलों और स्टेशनों की पेट्रोलिंग के लिए विशेष टीमें तैनात हैं और यात्रियों से अनुरोध किया गया है कि वे बिना आवश्यकता यात्रा से बचें।

तूफान मोंथा की गति और दिशा लगातार बदल रही है, जिससे तटीय राज्यों में चिंता का माहौल है। विशेषज्ञों के अनुसार, यह तूफान अगले 24 घंटों में और भी तेज़ी पकड़ सकता है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि आने वाले दिनों में परिस्थिति और गंभीर हो सकती है, इसलिए नागरिकों को सतर्क रहना और सुरक्षा निर्देशों का पालन करना आवश्यक है।

रूस का आरोप: यूक्रेन के मोर्चे पर विदेशी सैनिक सक्रिय—क्रेमलिन ने कहा, "हमें अंग्रेज़ी और फ्रांसीसी स्वर सुनाई दिए", NATO ने दावों को खारिज किया

मास्को। रूस ने मंगलवार को एक बार फिर तीखा बयान जारी करते हुए दावा किया कि यूक्रेनी मोर्चों पर न केवल स्थानीय बल बल्कि विदेशी सैनिक भी सक्रिय रूप से लड़ रहे हैं। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने प्रेस ब्रीफ़िंग में कहा कि रूसी सैनिकों को मोर्चे पर अंग्रेज़ी और फ्रांसीसी भाषाओं में वार्तालाप और आदेश सुनाई दिए गए हैं, जो इस बात की ओर संकेत हैं कि नाटो देशों के लड़ाके सीधा युद्धक्षेत्र में मौजूद हैं। पेस्कोव ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर यह प्रवृत्ति जारी रही तो रूसी सेना ऐसे तत्वों के ख़ात्मे के लिए पूरी तरह तैयार है — उनके शब्दों में, "जो भी विदेशी सैनिक हमारी सीमाओं पर आकर लड़ेंगे, उनका निश्चय ही सफाया किया जाएगा।" इस बयान ने तुरंत अंतरराष्ट्रीय कूटनीति में हलचल मचा दी और दोनों पक्षों के बीच गतिरोध और बढ़ गया।

रूस के इस दावे को नाटो और अमेरिका ने तुरंत खारिज कर दिया है। पश्चिमी राजनयिकों ने साफ कहा कि नाटो किसी भी तरह के लड़ाकू बल को यूक्रेन में तैनात नहीं कर रहा; हाँ, यूरोपीय और अमेरिकी खुफिया तथा सैन्य सलाहकार वहाँ उपस्थित हैं पर वे सीधे हथियार लेकर या पैदल सेनाओं की तरह लड़ाई में सम्मिलित नहीं हैं। अमेरिकी और यूरोपीय खुफिया अधिकारियों के बयान यह भी रहा कि उनकी एजेंसियाँ यूक्रेन को रणनीतिक और खुफिया सहायता देती हैं, परन्तु इसमें प्रत्यक्ष युद्धक भागीदारी नहीं आती। इन असहमति भरे बयानों के बीच वैश्विक स्तर पर एक बार फिर युद्ध-प्रवृत्ति और बदस्तूरी के आरोप-प्रत्यारोपों की बहस छिड़ गई है।

उसी समय यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने अंतरराष्ट्रीय समुदाय से सहायता की पुकार दोहराई और कहा कि उनका देश शांति वार्ताओं के लिए तैयार है, पर रूसी शर्तों पर नहीं। जेलेंस्की ने स्पष्ट किया कि वार्ता रूस या बेलारूस में आयोजित नहीं होगी और उन्होंने जोड़कर कहा कि यूक्रेन किसी भी हिस्से से पीछे हटने को तैयार नहीं है। उन्होंने अमेरिकी सांसदों से अपील करते हुए कहा कि रूस पर और कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाए जाएं ताकि आक्रमणकारियों को युद्ध जारी रखने की क्षमता क्षीण पड़े। जेलेंस्की ने यह भी माना कि यूक्रेन को आने वाले दो-तीन सालों तक युद्ध और पुनर्निर्माण दोनों के दबाव से पार पाने के लिए व्यापक आर्थिक सहायता की आवश्यकता होगी।

द्विपक्षीय बातचीत की संभावनाओं पर फिलहाल ठहराव सा दिख रहा है। कुछ दिनों पहले प्रस्तावित बुडापेस्ट वार्ता, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप और व्लादिमीर पुतिन के बीच परामर्श होने की बातें सामने आई थीं, रूस की तेज़ मांगों के कारण टल गई। यह टलन अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य में एक और चिंता का कारण बन गई है कि कहीं राजनयिक रास्ते पूरी तरह बंद न हो जाएं और संघर्ष और लंबा और घातक रूप न धारण कर ले। विश्लेषक मानते हैं कि रूस के दावे और पश्चिम के साथ उनके तीव्र संशय ने युद्ध-क्षेत्र के परिदृश्य को और भी जटिल बना दिया है। अगर विदेशी सैनिकों की उपस्थिति के आरोप सत्य भी माने जाएँ, तो भी यह प्रश्न उठता है कि क्या अंतरराष्ट्रीय समुदाय खुले तौर पर युद्ध में उतरने को राज़ी होगा; फिलहाल संकेत यही मिलते हैं कि पश्चिमी देश यूक्रेन को रूपांतरित समर्थन — हथियार, वित्तीय सहायता, प्रशिक्षण और खुफिया साझा करके — मदद कर रहे हैं, पर सीधे लड़ाकू बल तैनात करने से कतरा रहे हैं। दूसरी ओर, क्रेमलिन के अनुमानों और चेतावनियों ने रूस के भीतर भी राष्ट्रवादी धाराओं को बल दिया है और यह सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या मॉस्को किसी भी विदेशी हस्तक्षेप को रूस की सार्वभौमिक सुरक्षा के विरुद्ध सीधी चुनौती के रूप में लेगा और उसे उसी के अनुरूप जवाब देगा। स्थानीय और वैश्विक स्तर पर जनता और राजनेता दोनों चिंतित दिख रहे हैं। सीमावर्ती इलाकों में रहने वाले नागरिकों की सुरक्षा, ऊर्जा आपूर्ति के मुद्दे, और वैश्विक व्यापार-आश्रयों पर संभावित नकारात्मक प्रभाव — ये सभी ऐसे विषय हैं जिनका तुरन्त ध्यान रखना आवश्यक है। वहीं, यूक्रेन के राष्ट्रपति का यह आग्रह कि यूरोपीय और अंतरराष्ट्रीय सहयोग युद्ध के साथ-साथ देश के आर्थिक पुनर्निर्माण के लिए भी अनिवार्य है, वैश्विक सहायता का एक दीर्घकालिक एजेंडा सुझाता है।

अभी के लिए स्थिति कूटनीतिक और सैन्य दोनों मोर्चों पर तनावपूर्ण बनी हुई है। रूसी दावे, नाटो का इंकार, और यूक्रेन की शांति-ताकीद के बीच संतुलन बैठाना आसान नहीं दिख रहा। अंतरराष्ट्रीय समुदाय के सामने अब चुनौती यह है कि किस तरह सैन्य गतिरोध और आरोप-प्रत्यारोपों को कूटनीतिक प्लेटफ़ॉर्म पर लाकर वास्तविक वार्ता की तरफ़ मोड़ा जाए, ताकि क्षेत्रीय स्थिरता और मानवीय जटिलताओं का एक टिकाऊ समाधान निकाला जा सके।

राजस्थान में हाईटेंशन तारों से टकराई स्लीपर बस, भीषण आग में दो मजदूरों की मौत, कई झुलसे — दो सप्ताह में दूसरी बड़ी दुर्घटना से हिला प्रदेश

जयपुर। राजस्थान के जयपुर ज़िले के मनोहरपुर इलाके में मंगलवार को एक दर्दनाक हादसे ने पूरे प्रदेश को दहला दिया। एक निजी स्लीपर बस, जो उत्तर प्रदेश के पीलीभीत से 50 से अधिक मजदूरों को लेकर मनोहरपुर स्थित एक ईंट भट्ठे की ओर जा रही थी, अचानक हाईटेंशन बिजली के तारों के संपर्क में आ गई। चंद सेकंड में बस आग की भीषण लपटों में घिर गई। इस हादसे में दो मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 10 से अधिक लोग गंभीर रूप से झुलस गए।

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार बस की छत पर मोटरसाइकिल, साइकिल और घरेलू सामान रखा गया था। जब बस मनोहरपुर के एक कच्चे रास्ते से गुजर रही थी, तब ऊपर से गुजर रही हाईटेंशन लाइन से यह सामान टकरा गया। टकराते ही बिजली का करंट पूरे वाहन में फैल गया और कुछ ही पलों में आग ने बस को अपनी चपेट में ले लिया। बस के अंदर रसोई गैस सिलेंडर भी रखे थे, जिससे आग और भयावह हो गई। आग की तीव्रता इतनी अधिक थी कि कई मजदूरों को जान बचाने के लिए चलते वाहन से कूदना पड़ा।

स्थानीय ग्रामीणों ने मौके पर पहुंचकर किसी तरह बस में फंसे यात्रियों को निकालने की कोशिश की, लेकिन आग की लपटें लगातार बढ़ती जा रही थीं। प्रशासन ने फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस को मौके पर भेजा। घायलों को पहले शाहपुरा के सरकारी अस्पताल ले जाया गया, जहां से छह मजदूरों की गंभीर स्थिति को देखते हुए उन्हें जयपुर के एसएमएस अस्पताल रेफर किया गया।

जिला प्रशासन के अनुसार, दो गैस सिलेंडरों में आग लगने से विस्फोट जैसे हालात बने और इससे आग की तीव्रता कई गुना बढ़ गई। अधिकारियों का कहना है कि बस की संरचना में अवैध तरीके से बदलाव किए गए थे ताकि अधिक यात्री समा सकें। साथ ही, बस में कोई आपातकालीन निकास द्वार नहीं था, जिसकी वजह से कई मजदूर फंसे रह गए और झुलस गए।

मनोहरपुर के ग्रामीणों ने बताया कि कुछ मजदूर बस से उतरकर ड्राइवर को तारों से बचने का इशारा कर रहे थे, लेकिन ऊँचा सामान पहले ही तारों से छू गया और पूरा हादसा हो गया। इस हादसे के बाद क्षेत्र में दहशत का माहौल है।

संभागीय आयुक्त पूनम ने कहा कि यह जांच की जा रही है कि बस में गैस सिलेंडर, मोटरसाइकिल और अन्य सामान किस अनुमति के तहत ले जाए जा रहे थे। उन्होंने स्पष्ट किया कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इस घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया और घायलों के समुचित उपचार के निर्देश दिए हैं। उन्होंने जिला प्रशासन को तत्काल राहत और मुआवजे की प्रक्रिया शुरू करने का आदेश दिया। उपमुख्यमंत्री एवं परिवहन मंत्री प्रेमचंद बैरवा ने हादसे की जांच की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि "राज्य में इस तरह की लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बस मालिक और एजेंसी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।"

पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी घटना को दुखद बताया और कहा कि लगातार हो रही बस दुर्घटनाएँ राज्य में परिवहन सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर रही हैं।

गौरतलब है कि राजस्थान में यह दो सप्ताह के भीतर दूसरी बड़ी स्लीपर बस हादसा है। इससे पहले 14 अक्टूबर को जैसलमेर से जोधपुर जा रही एक निजी बस में आग लगने से कई यात्रियों की जान चली गई थी, जिसका कारण "शॉर्ट सर्किट" बताया गया था।

लगातार हो रही ऐसी घटनाओं ने राज्य में अवैध रूप से संशोधित बसों, सुरक्षा मानकों की अनदेखी और निगरानी तंत्र की विफलता पर गहरे प्रश्नचिह्न लगा दिए हैं। लोगों का कहना है कि जब तक इन नियमों के उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई नहीं की जाएगी, तब तक ऐसे हादसे रुकने वाले नहीं हैं।

नागपुर में पैसों के विवाद ने ली पिता की जान — बेटे ने लोहे की रॉड से पीट-पीटकर की हत्या, इलाके में सनसनी

नागपुर। शहर के एक शांत मोहल्ले में मंगलवार दोपहर एक ऐसी दिल दहला देने वाली वारदात हुई जिसने रिश्तों की पवित्रता को शर्मसार कर दिया। महज पैसों के विवाद ने एक बेटे को हैवान बना दिया। 22 वर्षीय युवक पवन उर्फ नेगी नारायण आरेमोरिकर ने अपने पिता नारायण दामोजी आरेमोरिकर (57) की लोहे की रॉड से बेरहमी से पीट-पीटकर हत्या कर दी। यह वारदात दोपहर करीब साढ़े बारह बजे उनके घर के भीतर घटी, जब आसपास के लोग कामकाज में व्यस्त थे। कुछ ही पलों में यह घरेलू झगड़ा एक भयानक हत्या में बदल गया और जब तक पड़ोसी मौके पर पहुंचे, पिता की सांसें थम चुकी थीं।

पुलिस के अनुसार, पिता-पुत्र के बीच पैसों को लेकर लंबे समय से मनमुटाव चल रहा था। मंगलवार को दोनों के बीच फिर किसी पुराने लेन-देन को लेकर कहासुनी शुरू हुई। नारायण आरेमोरिकर ने कथित तौर पर बेटे को डांटा और अपशब्द कहे। इससे पवन का गुस्सा बेकाबू हो गया। उसने घर में रखी लोहे की रॉड उठा ली और अपने पिता पर लगातार वार करता चला गया। बताया जा रहा है कि रॉड के वार इतने जबरदस्त थे कि मौके पर ही पिता की मौत हो गई।

घटना की खबर मिलते ही स्थानीय पुलिस तुरंत मौके पर पहुँची और आरोपी बेटे को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने हत्या में प्रयुक्त लोहे की रॉड भी बरामद कर ली है। अधिकारियों के अनुसार, प्रारंभिक जांच में यह बात सामने आई है कि परिवार आर्थिक तंगी से गुजर रहा था और इसी तनाव के चलते पिता-पुत्र के बीच अक्सर झगड़े होते थे।

पुलिस अब मामले की गहराई से जांच कर रही है। पड़ोसियों और रिश्तेदारों से पूछताछ की जा रही है ताकि हत्या के पीछे की असली पृष्ठभूमि सामने आ सके। जांच दल आरोपी की मानसिक स्थिति का भी मूल्यांकन कर रहा है, क्योंकि सूत्रों के मुताबिक वह पिछले कुछ महीनों से असामान्य व्यवहार कर रहा था।

इलाके के लोगों में इस वारदात को लेकर गहरा आक्रोश और भय का माहौल है। एक पड़ोसी ने कहा, "हमने कई बार पिता-पुत्र को झगड़ते सुना था, लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि बेटा इतना बेकाबू हो जाएगा कि अपने पिता की जान ले लेगा। ये सुनकर ही शरीर सिहर उठता है।"

स्थानीय समाजशास्त्रियों का कहना है कि यह घटना केवल एक पारिवारिक हत्या नहीं, बल्कि समाज में बढ़ते मानसिक तनाव, आर्थिक असंतुलन और संवाद की कमी की भयावह परिणति है। परिवारों के भीतर छोटी-छोटी बातों पर बढ़ते विवाद और गुस्से की अनियंत्रित अभिव्यक्ति अब खतरनाक रूप लेने लगी है।

एक पुलिस अधिकारी ने कहा, "यह सिर्फ एक अपराध नहीं, बल्कि समाज के लिए चेतावनी है कि मानसिक स्वास्थ्य और पारिवारिक संवाद की उपेक्षा किस हद तक विनाशकारी हो सकती है।"

पैसों की मामूली बात पर अपने पिता की जान लेने वाला पवन अब सलाखों के पीछे है, लेकिन इस घटना ने एक परिवार को हमेशा के लिए तोड़ दिया और समाज को एक गहरा सवाल दे दिया — आखिर हम कब सीखेंगे कि रिश्ते पैसों से बड़े होते हैं, और गुस्सा कभी समाधान नहीं होता।

1947 से अब तक सात वेतन आयोगों ने बदल दी सरकारी कर्मचारियों की तनख्वाह की तस्वीर, हर दौर में बढ़ता गया जीवन स्तर और जिम्मेदारियों का दायरा

नई दिल्ली। आजादी के तुरंत बाद 1947 में जब भारत एक नए राष्ट्र के रूप में अपनी प्रशासनिक संरचना को आकार दे रहा था, तब सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक थी — सरकारी कर्मचारियों के लिए एक न्यायसंगत, स्थायी और सम्मानजनक वेतन प्रणाली तय करना। इसी आवश्यकता से जन्म हुआ "वेतन आयोग" की परंपरा का, जिसने आने वाले दशकों में करोड़ों कर्मचारियों और पेंशनरों की जिंदगी को दिशा दी। स्वतंत्र भारत में अब तक सात वेतन आयोग बन चुके हैं, जिन्होंने देश की आर्थिक स्थिति, महंगाई, जीवन स्तर और सरकारी सेवाओं की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए समय-समय पर वेतन ढांचे में व्यापक बदलाव किए हैं।

पहला वेतन आयोग वर्ष 1946 में श्रीनिवास वरदाचारी की अध्यक्षता में गठित हुआ था। इस आयोग ने 1947 में अपनी रिपोर्ट दी और पहली बार सरकारी कर्मचारियों के लिए "लिविंग वेज" यानी जीवन निर्वाह योग्य वेतन का सिद्धांत प्रस्तुत किया। आयोग का उद्देश्य यह था कि सरकारी कर्मियों को इतना वेतन मिले जिससे वे अपने परिवार के साथ सम्मानजनक जीवन जी सकें। इस आयोग ने न्यूनतम वेतन 55 रुपये और अधिकतम वेतन 2,000 रुपये प्रति माह तय करने की सिफारिश की। यह वही दौर था जब भारत में प्रशासनिक ढांचा अभी स्थिर नहीं हुआ था, लेकिन इस आयोग ने सरकारी सेवा को आकर्षक और स्थायी बनाने की नींव रख दी।

दूसरा वेतन आयोग अगस्त 1957 में जगन्नाथ दास की अध्यक्षता में बना। उसने देश की आर्थिक प्रगति, मुद्रास्फीति और सार्वजनिक सेवाओं की बढ़ती जरूरतों को ध्यान में रखते हुए न्यूनतम वेतन 80 रुपये प्रति माह तय करने की सिफारिश की। आयोग ने यह भी कहा कि सरकारी कर्मचारियों की तनख्वाह ऐसी होनी चाहिए जिससे वे निजी क्षेत्र के कर्मचारियों से प्रतिस्पर्धा कर सकें और सेवा में उत्कृष्टता बनाए रखें।

तीसरे वेतन आयोग की स्थापना 1970 में रघुबीर दयाल की अध्यक्षता में की गई। यह वह समय था जब देश में औद्योगिक विकास और सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों का विस्तार हो रहा था। आयोग ने सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के बीच आय असमानता पर ध्यान केंद्रित किया और पे स्ट्रक्चर में समानता लाने का प्रयास किया। इस आयोग की रिपोर्ट ने वेतन के अनुपात में भत्तों और ग्रेड संरचना को एक नया स्वरूप दिया।

चौथा वेतन आयोग जून 1983 में पी. एन. सिंघल की अध्यक्षता में गठित किया गया। चार साल तक चले अध्ययन और विचार के बाद इस आयोग ने 1986 में अपनी रिपोर्ट सौंपी। इस आयोग ने न्यूनतम वेतन 750 रुपये मासिक तय किया और पहली बार परफॉर्मेंस-लिंक्ड पे स्ट्रक्चर की सिफारिश की, ताकि कर्मचारियों के कार्य प्रदर्शन का सीधा प्रभाव उनके वेतन और पदोन्नति पर पड़े।

पांचवां वेतन आयोग 1994 में गठित हुआ और इसकी अध्यक्षता जस्टिस एस. रत्नावेल पांडियन ने की। इस आयोग ने सरकारी खर्चों को नियंत्रित करने और प्रशासनिक ढांचे को आधुनिक बनाने पर बल दिया। आयोग ने सरकारी कर्मचारियों की संख्या घटाने, अनावश्यक पदों को समाप्त करने और पे स्केल की विविधता कम करने की सिफारिश की। साथ ही, सूचना प्रौद्योगिकी को सरकारी कार्यालयों में शामिल करने की सलाह दी, जिससे कार्यकुशलता बढ़ाई जा सके।

छठे वेतन आयोग ने 2006 में न्यायाधीश बी. एन. श्रीकृष्णा के नेतृत्व में एक नई सोच के साथ वेतन संरचना का पुनर्निर्धारण किया। मार्च 2008 में पेश की गई इस रिपोर्ट ने वेतन प्रणाली में सबसे बड़ा बदलाव लाया — रनिंग पे बैंड और ग्रेड पे की अवधारणा। इसका उद्देश्य पे स्केल को सरल बनाना और विभिन्न कैडरों के बीच समानता लाना था। साथ ही, आयोग ने "परफॉर्मेंस-बेस्ड इन्सेंटिव" पर भी जोर दिया, ताकि दक्ष कर्मचारियों को अतिरिक्त प्रोत्साहन मिल सके।

सातवां और अब तक का नवीनतम वेतन आयोग वर्ष 2016 में लागू हुआ। इसकी सिफारिशें 1 जनवरी 2016 से प्रभावी हुईं। आयोग ने कुल 23.55 प्रतिशत की वृद्धि वेतन, भत्तों और पेंशन में की। न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये मासिक तय किया गया और फिटमेंट फैक्टर 2.57 निर्धारित किया गया। इस आयोग ने डिजिटल युग में कार्यरत सरकारी कर्मचारियों के लिए आधुनिक और पारदर्शी वेतन प्रणाली विकसित की।

आजादी के बाद से लेकर अब तक इन सातों वेतन आयोगों ने न केवल कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि की है, बल्कि प्रशासनिक सोच को भी बदल दिया है। पहले जहाँ ध्यान जीवन निर्वाह योग्य वेतन पर था, वहीं अब फोकस दक्षता, प्रदर्शन, पारदर्शिता और परिणाम आधारित सेवा पर है।

इन आयोगों की सिफारिशों ने सरकारी कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ किया है और देश के सामाजिक ढांचे में स्थिरता प्रदान की है। आने वाले समय में जब आठवें वेतन आयोग की चर्चा शुरू होगी, तो वह सिर्फ वेतन बढ़ोतरी का नहीं, बल्कि डिजिटल गवर्नेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और कार्यकुशल प्रशासन के युग में "स्मार्ट सर्विस स्ट्रक्चर" की दिशा में एक नया कदम होगा।

"मुख्यमंत्री पद की कोई वैकेंसी नहीं"—रविशंकर प्रसाद का बयान, कहा नीतीश कुमार ही रहेंगे एनडीए का चेहरा, विपक्ष पर साधा निशाना

पटना। बिहार की सियासत में मुख्यमंत्री पद को लेकर चल रही अटकलों के बीच भारतीय जनता पार्टी ने स्पष्ट कर दिया है कि एनडीए में नेतृत्व को लेकर किसी भी तरह की शंका या बदलाव की गुंजाइश नहीं है। पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने मंगलवार को कहा कि मुख्यमंत्री पद के लिए कोई "वैकेंसी" नहीं है और नीतीश कुमार ही एनडीए के सर्वमान्य नेता हैं। उन्होंने कहा, "नीतीश कुमार पिछले दो दशकों से एनडीए के नेता हैं और आगे भी रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की जोड़ी चट्टान की तरह मज़बूत है, जिसे कोई हिला नहीं सकता।"

रविशंकर प्रसाद के इस बयान को बिहार की राजनीति में चल रही उस हलचल के जवाब के रूप में देखा जा रहा है, जिसमें विपक्ष लगातार यह सवाल उठा रहा था कि आगामी विधानसभा चुनावों में एनडीए की ओर से मुख्यमंत्री पद का चेहरा कौन होगा। इस बयान के साथ भाजपा ने न केवल राजनीतिक संदेश दिया है, बल्कि यह संकेत भी दे दिया है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व पर सवाल उठाने वालों को कोई मौका नहीं दिया जाएगा।

विपक्ष पर पलटवार करते हुए रविशंकर प्रसाद ने महागठबंधन और आरजेडी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि जो लोग "बिहार को नया विजन देने" की बात कर रहे हैं, वे खुद भ्रष्टाचार के प्रतीक हैं। उन्होंने लालू यादव के परिवार पर निशाना साधते हुए कहा कि "आरजेडी आज भ्रष्टाचार की पाठशाला बन चुकी है। परिवारवाद और लूट की राजनीति बिहार को फिर अंधकार में धकेल देगी। जो लोग नैतिकता की बात करते हैं, उनके खिलाफ सीबीआई और ईडी की दर्जनों जांचें चल रही हैं।"

वक्फ कानून को लेकर भी उन्होंने विपक्ष की आलोचना की और कहा कि यह संसद द्वारा पारित कानून है, इसे फाड़ना न केवल संविधान के खिलाफ है बल्कि लोकतंत्र की मर्यादाओं का भी अपमान है। उन्होंने विपक्षी दलों को चेतावनी देते हुए कहा कि "कानून तोड़ने की राजनीति" से बिहार के विकास को रोका नहीं जा सकता।

वहीं, इस राजनीतिक खींचतान के बीच आरजेडी नेता और पूर्व उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने एनडीए से सवाल किया था कि उनकी ओर से मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार कौन होगा। तेजस्वी ने कहा, "महागठबंधन ने तो अपना चेहरा पहले ही साफ कर दिया है, लेकिन एनडीए अब तक दुविधा में है। जनता जानना चाहती है कि आखिर उनके पास नेतृत्व कौन करेगा।"

तेजस्वी के इस बयान के कुछ ही घंटों बाद रविशंकर प्रसाद का यह जवाब सामने आया, जिसे एनडीए की ओर से "साफ राजनीतिक संकेत" माना जा रहा है कि नीतीश कुमार की कुर्सी फिलहाल पूरी तरह सुरक्षित है।

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि भाजपा का यह रुख आगामी चुनावों से पहले गठबंधन की एकजुटता दिखाने की कोशिश है। पिछले कुछ महीनों में बार-बार यह कयास लगाए जा रहे थे कि भाजपा बिहार में अपना अलग नेतृत्व खड़ा कर सकती है, लेकिन इस बयान के साथ फिलहाल उन सभी अटकलों पर विराम लग गया है।

बिहार की राजनीति में जहां विपक्ष "युवा चेहरा" बनाम "पुराना नेतृत्व" की बहस को हवा देने की कोशिश कर रहा है, वहीं एनडीए इस बयान के ज़रिए स्थिरता, अनुभव और विकास की राजनीति का संदेश देना चाह रहा है। अब देखना यह होगा कि क्या नीतीश-मोदी की यह जोड़ी एक बार फिर बिहार की सत्ता में वापसी करती है या विपक्ष अपनी रणनीति से राजनीतिक समीकरण बदलने में कामयाब होता है।